सतना
25 जुलाई 2026 शुक्रवार

दैनिक मीडियाऑडीटर

सतना, रीवा एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

सीजेपी बोली- प्रधान के इस्तीफे पर सरकार आज जवाब देगी

नई दिल्ली,एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और CJP की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए।

बैठक के बाद CJP के प्रवक्ताओं ने कहा,'हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है।'

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया, 'दो घंटे की बातचीत में CJP ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगें और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमनें ने इस पर विचार करने के लिए आज का समय मांगा है।'

सुसाइड करने वाले हृश्वश्वञ्ज छात्रों के परिवार को मुआवजा देने और केस वापस लेने को तैयार

छात्रों पर पुलिस की ज्यादती, अर्जी सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर लीक के खिलाफ विरोध कर रहे छात्रों पर पुलिस की ज्यादती के आरोपों वाली दो अलग-अलग याचिकाओं पर 27 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई।यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने उठाया गया।

सीजेपी ने सरकार को पत्र सौंपा, तीन मांगे

सीजेपी ने शुक्रवार को सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर अपनी मांगों का पत्र सौंपा। पत्र के मुताबिक, उसकी मांगों में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, NEET पीड़ितों को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करना शामिल है।पत्र में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार, रैपिड एक्शन फोर्स के प्रमुख और दिल्ली पुलिस आयुक्त को उन छात्रों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, जिन्हें पीटा गया।

पीएम का रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश

मोदी ने कहा- पेपर लीक पर कैबिनेट सख्त फैसला लेगी, जल्द बिल पास

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान करने वाला कानून बनाएगी।

पीएम ने बताया कि कैबिनेट में इससे जुड़े मसौदे पर आज चर्चा होगी और सख्त फैसले लिए जाएंगे। मंजूरी मिलने के बाद इसे अगले हफ्ते संसद में पेश किया जाएगा। साथ ही इसे जल्द पास कराने की कोशिश होगी।

पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर 2.56 मिनट का एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया। कहा- पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों छात्रों, उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक से अब तक, पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं। हमारी जिम्मेदारी थी कि छात्रों का साल बर्बाद न हो, इसलिए कम समय में 22 लाख छात्रों का एग्जाम कराया। 19 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया।

उन्होंने यह भी कहा- हम इतने से संतोष करने वाले नहीं हैं। इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश दिया है। विभागों ने देर रात मुझे मसौदा भेजा है। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान हैं।

सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल 27वें दिन खत्म

» नड्डा ने जूस पिलाया; वांगचुक बोले- तीन मांगों पर लिखित आश्वासन मिला, इनमें प्रधान का इस्तीफा शामिल नहीं

नई दिल्ली,एजेंसी। नीट पेपर लीक के खिलाफ 27 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने गुरुवार देर रात अपना अनशन खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां नड्डा ने वांगचुक को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। वांगचुक ने शुक्रवार सुबह जारी वीडियो संदेश में कहा कि पिछले दो दिन से सरकार के साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही थी। इस दौरान उनकी तीन प्रमुख मांगों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से इन मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। वांगचुक ने कहा, सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर केस दर्ज नहीं करने, पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने के मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजन को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया।

वांगचुक ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया है। उनके लिए सबसे अहम बात छात्रों पर कार्रवाई रुकवानी थी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इतना जरूरी नहीं था। वांगचुक के अनशन खत्म करने पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) फाउंडर अभिजीत दीपके ने खुशी जताई। हालांकि, उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर-मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा।

विपक्षी सांसदों ने भी मिलकर अनशन खत्म करने को कहा था: 22 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचा, जहां सोनम वांगचुक भर्ती थे। प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के विवेक तन्खा, तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष, सीपीआई(एम) के जॉन ब्रिटास, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह समेत कई सांसद शामिल थे।

वायुसेना की तैनाती स्थायी ईलाज नहीं':सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली,एजेंसी। नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और गलतियों के सिलसिले को तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाते हुए केंद्र से पूछा कि पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड (CBT) में बदलने और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष पूरी स्थिति और रोडमैप रखने के लिए कुछ और समय की मांग की है।

हलफनामा दाखिल करने का निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को NEET-UG पेपर लीक के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि हलफनामे में कामचलाऊ उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया जाना चाहिए।

कोर्ट ने प्रस्तावित गवर्निंग बोर्ड, विशेषज्ञों के नेतृत्व वाली इकाइयों, स्टेकहोल्डर के नामांकन और दस क्षेत्रों (जिनमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा, रिसर्च और डेवलपमेंट, पारदर्शिता, प्रशासन और मानव संसाधन शामिल हैं) में हाई-पावर्ड कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के बारे में जानकारी मांगी।

कोर्ट ने केंद्र से राज्य और जिला अधिकारियों के साथ टेस्टिंग के तरीकों, कई सेशन में होने वाली परीक्षाओं, परीक्षा केंद्रों, प्रश्न पत्रों, प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन पर हुई प्रगति के बारे में भी बताने को कहा।

कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट... कोर्ट ने केंद्र से सुरक्षा, निगरानी और सतर्कता के लिए हाल ही में नियुक्त अतिरिक्त महानिदेशकों की भूमिका और प्रगति के बारे में भी बताने को कहा और परीक्षा चक्र के हर चरण– परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के बाद में सुधारों पर स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी।

राहुल बोले- संसद में बोलने से रोका, माइक बंद किया

रिजिजू ने कहा- हम चर्चा को तैयार, सदन चलने दें; राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश

नई दिल्ली,एजेंसी। लोकसभा में नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा- हम सदन में चर्चा को तैयार हैं।

विपक्ष से अपील है कि सदन को चलने दें, राहुल गांधी अपने सांसदों को समझाएं। उधर राहुल ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। मेरा माइक बंद कर दिया गया।

विपक्षी सांसदों ने सदन में इस्तीफा-इस्तीफा के नारे लगाए। विपक्ष की मांग है कि, पीएम सदन में माफी मांगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाएं।

इधर, गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश कर दिया। हालांकि यह अभी पारित नहीं हुआ। हंगामे के चलते दोनों सदन 27 जुलाई तक स्थगित कर दिए गए।

राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा बिल पेश किया गया

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में 'राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026' पेश किया। यह विधेयक राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में संशोधन से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन के तहत 'वंदे मातरम' के अपमान या उसके गायन में जानबूझकर बाधा डालने को दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया गया है।

राहुल बोले: प्रधान के इस्तीफे तक कोई चर्चा नहीं करेंगे

राहुल गांधी ने कहा, जब तक प्रधान को हटाया नहीं जाता, हम कोई बातचीत या चर्चा नहीं करेंगे। रिजिजू ने बयान दिया कि वह हमारे सांसदों को बताना चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए। सामान्य नियम यह है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है, तो उसका जवाब दिया जाता है। जब मैं जवाब देना चाहता था, तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। मुझे मौका नहीं दिया गया।

रिजिजू बोले: हम आज ही सदन में चर्चा को तैयार

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा, मैंने आज एक बार फिर केसी वेणुगोपाल जी से अनुरोध किया है, क्योंकि हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि NEET पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिलाया है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और चर्चा की मांग की है। अगर हम चर्चा नहीं करते हैं, तो इससे देश में सही संदेश नहीं जाएगा।

नीट पेपर लीक मामले में देशभर में विरोध प्रदर्शन

यूपी-हरियाणामें जुलूस निकाले

नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार में छात्रों का प्रदर्शन जारी है। पटना में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बक्सर में छात्र पोस्टर-बैनर लेकर सड़कों पर उतरे हैं। राजस्थान के जयपुर में में वकील धरने पर बैठे हैं।

: ब्रीफ बॉक्स :

सऊदी से परमाणु समझौता करके 24 घंटे में पलटे ट्रम्प

वॉशिंगटन डीसी,एजेंसी। अमेरिका और सऊदी अरब के बीच करीब दो दशक से अटके परमाणु समझौते पर बुधवार को हस्ताक्षर हुए, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही यह डील अटक गई है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने समझौते में नई शर्त जोड़ दी है। उन्होंने कहा कि डील तभी आगे बढ़ेगी, जब सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल होकर इजराइल से राजनयिक रिश्ते सामान्य करेगा। ट्रम्प ने यह भी कहा कि सऊदी अरब को यूरेनियम संवर्धन (एनरिचमेंट) की अनुमति नहीं मिलेगी।

बिना बताए डील की घोषणा से ट्रम्प नाराज: वॉशिंगटन में हुए हस्ताक्षर समारोह में अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट शामिल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रम्प इस बात से नाराज थे कि राइट ने उनकी मंजूरी के बिना समझौते की घोषणा कर दी। इसके बाद फॉक्स न्यूज और वॉल स्ट्रीट जर्नल में हुई आलोचना से उनकी नाराजगी और बढ़ गई।

गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन

बोले: मत करें चिंता, सबकी समस्या पर होगी प्रभावी कार्रवाई

गोरखपुर,एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन, शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया। जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस अवसर पर उन्होंने समस्या-शिकायत लेकर आए लोगों को भरोसा देते हुए कहा, 'चिंता मत करें, सबकी समस्या पर प्रभावी कार्रवाई कराई जाएगी।' मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि यहां आई शिकायतों का निस्तारण और समस्याओं का समाधान शीघ्रता से कराया जाए।

शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 150 लोगों से मिले। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर लगी कुर्सियों पर बैठाए गए लोगो तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर उनकी समस्याओं को सुना, उनके प्रार्थना पत्र लिए।

उन्होंने पास में खड़े अधिकारियों को समस्या समाधान हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए। अलग-अलग मामलों से जुड़े समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण निष्पक्ष और समयबद्ध होना चाहिए। अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके साथ ही इलाज के लिए आर्थिक मदद से जुड़े प्रार्थना पत्रों पर उन्होंने अस्पतालों के इस्टीमेट की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा।

सीएम ने लोगों को आश्वस्त किया कि इस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को खूब दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया।

सीएम की आवाज सुन दौड़ते चले आए गोवंश: गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शुक्रवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर की गोशाला में जाकर गोसेवा की।

गोशाला में सीएम योगी ने भ्रमण करते हुए कुछ गोवंश को उनके नामों से पुकारा।

अमेरिका ने भारत पर 10प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया

जबरन मजदूरी से बने सामान को लेकर कार्रवाई, 60 देशों पर एक्शन

वॉशिंगटन डीसी,एजेंसी। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह फैसला शुक्रवार से लागू हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के निर्देश पर अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) ने फोर्स्ड लेबर (जबरन मजदूरी) से बने सामान के आयात को लेकर 60 देशों पर कार्रवाई की है। अमेरिका ने इन देशों पर 10% से 12.5% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। भारत उन 17 देशों में शामिल है, जिन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। वहीं बाकी 43 देशों पर 12.5% अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने यह कार्रवाई ट्रेड एक्ट-1974 की धारा 301 के तहत की है।

भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मेक्सिको, पाकिस्तान और श्रीलंका समेत कई देशों को 10% टैरिफ वाले समूह में रखा गया है। अमेरिका का कहना है कि इन देशों ने फोर्स्ड लेबर से बने सामान पर प्रतिबंध लगाया है या ऐसा करने की दिशा में कदम उठाए हैं।

भारत के किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है: अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। ऐसे में अतिरिक्त 10% टैरिफ से उन सेक्टरों पर ज्यादा असर पड़ सकता है, जिनकी अमेरिकी बाजार पर निर्भरता अधिक है।

ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका

ट्रम्प बोले- फैसला लेना बाकी; ईरान ने कहा- इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी, एजेसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर सबसे बड़ा हमला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, 'तैयारी पूरी है, अब सिर्फ फैसला लेना बाकी है।' ट्रम्प ने यह भी कहा कि ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला है।

ट्रम्प के बयान के बाद ईरान ने भी तुरंत जवाब दिया। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अगर अमेरिका ने हमले जारी रखे तो उसे इसकी 'और भारी कीमत' चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने का रास्ता बातचीत है, नए हमले नहीं। इधर, ब्रिटेन ने भी अपनी सेना को अलर्ट पर रखा है।

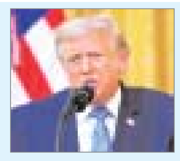

ईरान बोला- अमेरिकी हमलों के बावजूद बातचीत का रास्ता खुला... ईरान के एक वरिष्ठ राजनयिक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिकी हमलों के बावजूद कूटनीति का रास्ता खुला है। अल जजीरा से बातचीत में अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान–प्रदान जारी है। अधिकारी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ईरान के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है, जिससे कूटनीतिक प्रयास प्रभावित हुए हैं।

गुजरात के नवसारी में बाढ़, हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट

अहमदाबाद-सूरत समेत 5 शहरों में पानी भरा, बाजार डूबे

● यूपी में सड़क पर नाव चली, असम में बाढ़ से 47 मौत

नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर,एजेंसी। देश के कई हिस्सें में भारी बारिश हो रही है। कई जगह बारिश के पानी में गाड़ियां बह गई है। असम के कई हिस्से बाढ़ के कारण अभी भी जलमग्न हैं। अधिकारियों ने बताया कि 11 जिले बाढ़ की चपेट में आए हैं। इससे 7.21 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं, मरने वालों की संख्या 47 हो गई है।

पूरे देश में मानसून की बारिश जारी है। दक्षिण गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वलसाड के उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं। शुक्रवार को राज्य के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नवसारी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। अहमदाबाद, सूरत में पानी भर गया। वाव-थराद जिले में बाजार डूब गए।

यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। सीतापुर में पानी सड़क पर भर गया। ग्रामीण नाव से आ-जा रहे हैं। पटना, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली और सिवान समेत बिहार के 19 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

पंजाब बना देशभर में तस्करी नेटवर्क का रास्ता, बॉर्डर से शहरों तक नशे का जाल; संसद में रिपोर्ट में हुए खुलासे

चंडीगढ़, एजेंसी। पाकिस्तान से पंजाब सीमा के रास्ते ड्रोन के माध्यम से भेजी जा रही हेरोइन अब केवल सीमावर्ती जिलों तक सीमित नहीं रह गई है। जांच एजेंसियों के अनुसार पंजाब पहुंचने के बाद संगठित तस्करी नेटवर्क इस खेप को देश के कई राज्यों तक पहुंचा रहा है।

राज्यसभा में केंद्र सरकार ने भी स्वीकार किया है कि ड्रोन के जरिए होने वाली नशा तस्करी का सबसे अधिक दबाव पंजाब सीमा पर है और बरामद नशीले पदार्थों में सबसे बड़ा हिस्सा हेरोइन का है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2025 में देशभर में ड्रोन के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के 305 मामले सामने आए।

इनमें 298 मामले केवल पंजाब सीमा से जुड़े थे। इन मामलों में करीब 460 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए गए, जिनमें 448 किलोग्राम हेरोइन, नौ किलोग्राम मेथामफेटामाइन और तीन किलोग्राम अफीम शामिल थी।यानी ड्रोन के जरिए बरामद कुल

नशीले पदार्थों में लगभग 97 प्रतिशत हिस्सा हेरोइन का रहा।

सीमावर्ती इलाकों से आगे पहुंचती है खेप: जांच एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब के सीमावर्ती इलाकों अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का और गुरदासपुर में गिराई गई खेप को स्थानीय तस्कर पहले सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क नेटवर्क के माध्यम से इसे विभिन्न राज्यों में सक्रिय गिरोहों तक भेजा जाता है। एनसीबी की इंडिया नारकोटिक्स थ्रेट असेसमेंट-2024, एनआईए तथा पंजाब पुलिस की जांच में पंजाब को अंतरराज्यीय तस्करी का प्रमुख ट्रांजिट कारिडोर बताया गया है। तस्कर अब केवल ड्रोन पर निर्भर नहीं हैं। वे संपर्क बनाए रखने, खेप की आवाजाही का समन्वय करने, तस्वीरें और वीडियो साझा करने तथा वास्तविक समय की लोकेशन भेजने के लिए गुप्त संदेश मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

वीपीएन से छिपती है पचहान

पहचान छिपाने के लिए आभासी निजी नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग किया जा रहा है, जबकि नशे के कारोबार से अर्जित धन के लेनदेन में डिजिटल मुद्रा और अन्य आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों का सहारा लिया जा रहा है। विदेशों में संचालित डिजिटल विनिमय मंचों के कारण धन के स्रोत तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। कुछ मामलों में जेलों में बंद तस्कर भी मोबाइल फोन के जरिए अपने सहयोगियों के संपर्क में रहकर नेटवर्क का संचालन करते पाए गए हैं। इसी कारण जांच एजेंसियां अब केवल सीमा पर निगरानी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय लेनदेन की भी गहन जांच कर रही हैं।

राज्यसभा में सरकार द्वारा दी गई जानकारी

तस्कर संपर्क और नेटवर्क संचालन के लिए गुप्त संदेश मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहचान छिपाने के लिए आभासी निजी नेटवर्क (वीपीएन) का उपयोग किया जा रहा है। नशे के कारोबार से अर्जित धन के लेनदेन में डिजिटल मुद्रा और आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों का इस्तेमाल बढ़ा है। जेलों में बंद कुछ तस्कर भी मोबाइल फोन के जरिए अपने सहयोगियों के संपर्क में रहकर नेटवर्क का संचालन करते पाए गए हैं। सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली, बंद परिपथ कैमरे, दूर से घूमकर निगरानी करने वाले कैमरे, रात्रि दृष्टि उपकरण, नई डिजाइन की सीमा बाड़ और फ्लड लाइट व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है।

नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर के घर खरीदारों को झटका, रिफंड याचिका पर सुनवाई तीन माह के लिए टली

नोएडा, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के ध्वस्त किए गए ट्विन टावर के घर खरीदारों को रकम वापस दिलाने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई तीन माह के लिए टाल दी है। कोर्ट ने उन दलीलों पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि जिन घर खरीदारों ने वैकल्पिक आवंटन का विकल्प नहीं चुना है, उनके दावों का निपटारा करने का प्रयास जारी है। पीठ से अनुरोध किया गया था कि खरीदारों के दावों के समाधान के लिए अन्य विकल्प तलाशने की खातिर तीन माह का समय दिया जाना चाहिए। इसके बाद पीठ ने सुनवाई टाल दी। ज्ञात हो, नोएडा के सेक्टर 93ए में एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के ट्विन-टावर को 28 अगस्त, 2022 को विस्फोटकों का प्रयोग करके ध्वस्त कर दिया गया था। कुछ घर खरीदारों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने कहा,उन्हें धनराशि वापस नहीं मिली है। आखिरी भुगतान 2024 में ही किया गया था। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि ट्विन टावर के घर खरीदारों को अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा जमा कराई गई राशि में से आनुपातिक आधार पर धन वापसी की जाएगी। कंपनी दिवाला प्रक्रिया का सामना कर रही है।

उत्तराखंड में जंगल की आग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का आदेश किया रद, दोबारा विचार के लिए वापस भेजा

देहरादून, नईदिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट के 2016 के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें जंगल की आग को नियंत्रित करने और रोकने समेत कई निर्देश दिए गए थे। शीर्ष अदालत ने मामले को दोबारा विचार के लिए हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल की आग से जुड़े मामलों में लगातार निगरानी की जरूरत होती है। हाई कोर्ट इनसे निपटने के लिए ज्यादा बेहतर स्थिति में है। पीठ ने ध्यान दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2017 में हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट को अपने निर्देशों पर फिर से विचार करना चाहिए। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि लगभग एक दशक बीत चुका है और जाहिर है कि समय के साथ जमीनी स्तर पर काफी बदलाव आया है।

सिर्फ महिलाओं' वाले टूर में पुरुषों को भी भेजा, ट्रैवल कंपनी पर जुर्माना

मुंबई, एजेंसी। मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बेंगलुरु की एक ट्रैवल कंपनी को सेवा में कमी और भ्रामक प्रचार का दोषी मानते हुए 60 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने कंपनी को मानसिक पीड़ा और असुविधा के लिए 40 हजार रुपये तथा मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 20 हजार रुपये देने को कहा है। मामला थाईलैंड के

उस पैकेज टूर से जुड़ा है, जिसका प्रचार सिर्फ महिलाओं के लिए के रूप में किया गया था, लेकिन यात्रा के दौरान उसी समूह में पुरुष और परिवारों को भी शामिल किया गया। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने बुकिंग के बाद बिना सहमति यात्रा कार्यक्रम बदल दिया। पैकेज में शामिल जेम्स बांड आइलैंड और फी-फी आइलैंड की सैर रद कर पर्यटकों को कोरल आइलैंड ले जाया गया। इसके अलावा, वादे के अनुरूप चार सितारा होटल के बजाय तीन सितारा होटल में ठहराया गया और भोजन व अन्य व्यवस्थाओं में भी गंभीर खामियां रहीं। आयोग ने इसे उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सेवा में कमी और अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना।चेंबूर निवासी महिला ने जनवरी 2025 में फुकेत और क्राबी के चार रात-पांच दिन के टूर के लिए 99,500 रुपये का पैकेज बुक कराया था। उनका कहना था कि यात्रा शुरू होने से दो दिन पहले कार्यक्रम बदल दिया गया, लेकिन 100 प्रतिशत रदीकरण शुल्क की शर्त के कारण उनके पास यात्रा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मामले की सुनवाई के दौरान ट्रैवल कंपनी आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आयोग ने माना कि कंपनी अपने वादों के अनुरूप सेवाएं देने में विफल रही।

दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, एक लाख करोड़ से अधिक की परियोजनाएं शुरू

नईदिल्ली, एजेंसी। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं शुरू की हैं। इससे कुल 2,105 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। यह जानकारी 23 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दक्षिणी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी की ओर से पूछे गए प्रश्न के जवाब में लिखित में दी। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दक्षिण दिल्ली की

परियोजनाओं की भी जानकारी मांगी थी। जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे की योजना के अंतर्गत डीएनडी से फरीदाबाद और सोहना होते हुए छह लेन का ग्रीनफील्ड करिडोर बनाया जाएगा, जिसकी लागत 4,583 करोड़ रुपए है। इसके अलावा लगभग सात हजार करोड़ रुपए की लागत से द्वारका एक्सप्रेस वे और एनएच-48 को नेल्सन मंडेला मार्ग (वसंत कुंज) से जोड़ने के लिए शिवमूर्ति से छह लेन की टनल भी शामिल है।

इंटरचेंज के निर्माण की अन्य परियोजनाओं का प्रस्ताव: वहीं आश्रम से बदरपुर बार्डर तक, महरौली-गुरुग्राम रोड, आइएनए से महिपालपुर और कालिंदी कुंज जंक्शन से ओखला बैराज तक इंटरचेंज के निर्माण की अन्य परियोजनाओं का प्रस्ताव है। इन परियोजनाओं में वर्तमान करिडोर का अपग्रेडेशन और विकास भी शामिल है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 20 साल बाद दोषी को किया बरी

नई दिल्ली, एजेंसी। वर्ष 2006 के एक अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहते हुए बरी कर दिया कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपित का अपराध संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। न्यायमूर्ति विमल कुमार यादव की पीठ ने कहा कि गवाहों के बयानों में अहम विरोधाभास, फोरेंसिक साक्ष्यों की कमजोरी और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपित को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। पीठ ने उक्त टिप्पणी के साथ अपीलकर्ता राम चंदर की अपील को स्वीकार कर लिया और उन्हें वर्ष 2008 में भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 363 (अपहरण) और 376 (दुष्कर्म) के तहत दोषी करार देकर सजा देने को रद कर दिया। अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि युवती अपनी इच्छा से उसके साथ गई थी ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दुष्कर्म के लिए सात वर्ष के कठोर कारावास और अपहरण के लिए एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी। आरोप है कि वर्ष 2006 में 13 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी और बाद में आरोपित के साथ बरामद हुई थी। वहीं, अपीलकर्ता ने तर्क दिया था कि युवती अपनी इच्छा से उसके साथ गई थी और घटना के समय वह बालिग थी।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग करने की बड़ी साजिश नाकाम; मास्टरमाइंड फैजान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

श्रीनगर, एजेंसी। देश की सुरक्षा और अखंडता पर घात लगाने वाले डिजिटल नेटवर्क के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कड़ा प्रहार किया है। गुजरात से संचालित हो रहे खतरनाक ऑनलाइन कट्टरपंथ नेटवर्क के मुख्य आरोपित फैजान के खिलाफ एनआईए ने अहमदाबाद की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह सिर्फ एक आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र नहीं है, बल्कि उस गहरे और नफरती तंत्र का भंडाफोड़ है जो इंटरनेट मीडिया के जरिये भारतीय युवाओं के दिलों में जहर घोलने की साजिश रच रहा था। एजेंसी का आरोप है कि उसने हिंसक जिहाद को बढ़ावा देने की साजिश रची, टारगेटेड किलिंग (चुनिंदा लोगों की हत्या) की योजना बनाई और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख को भारत से अलग करने की दिशा में काम किया। पाकिस्तानी हैंडलर से साठगांठ

और कत्ल की साजिश एनआइए की जांच में यह खौफनाक सच सामने आया है कि फैजान सीधे तौर पर पाकिस्तान में बैठे प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर और अल-कायदा से जुड़ा हुआ था। उसका मकसद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग करने की देशविरोधी साजिश को अंजाम देना था। इतना ही नहीं, देश में सांप्रदायिक तनाव और अराजकता फैलाने के लिए उसने चुनिंदा लोगों की 'टारगेट किलिंग' की भी रणनीति बनाई थी। इस खूनी खेल को अंजाम देने के लिए उसने उत्तर प्रदेश से अवैध हथियार और छह जिंदा कारतूस भी जुटाए थे, जिन्हें जांच के दौरान जब्त कर लिया गया है।

इंटरनेट मीडिया बना 'नफरत का औजार'

फैजान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (अल डाट फैजानगजा) का इस्तेमाल मासूम और भोले-भाले युवाओं को बरगलाने के लिए कर रहा था। वह हिंसक जेहाद और सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देने वाले खतरनाक वीडियो अपलोड करता था और युवाओं को लालच देकर भड़काता था। डिजिटल फॉरेंसिक जांच में उसके डिवाइस से ऐसे कई आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें बरामद हुई हैं, जो उसके काले कारनामों की गवाही देती हैं। गुजरात एटीएस द्वारा शुरू की गई इस जांच को मार्च में एनआईए ने संभाला था। यूएपीए, बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज यह मामला देश को बांटने वाली ताकतों के मुंह पर एक करारा थप्पड़ है। एजेंसी अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य चेहरों और सीमा पार बैठे आकाओं को बेनकाब करने में जुटी है।

दिल का भी होता है 'छोटा दिमाग': तनाव में भी धड़कन को रखता है सामान्य; आखिर कैसे करता है काम

संयुक्त राष्ट्र, एजेंसी। हृदय केवल मस्तिष्क के आदेश पर ही काम नहीं करता, बल्कि उसके भीतर मौजूद अपना एक सूक्ष्म तंत्रिका तंत्र भी उसकी धड़कनों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूहों पर किए गए एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया है कि हृदय के भीतर मौजूद कुछ विशेष तंत्रिका कोशिकाएं तनाव की स्थिति में भी दिल की सामान्य कार्यप्रणाली बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। यह खोज भविष्य में हृदय रोगों के अधिक सटीक और प्रभावी उपचार विकसित करने का रास्ता खोल सकती है।

तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है: जर्नल सेल में प्रकाशित इस अध्ययन में येल यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने हृदय के भीतर मौजूद आंतरिक तंत्रिका तंत्र (इंट्रिंसिक कार्डियक नर्वस सिस्टम) का विस्तृत

अध्ययन किया। शोधकर्ताओं का कहना है कि अब तक यह माना जाता था कि हृदय की अधिकांश तंत्रिका कोशिकाएं लगभग एक जैसी होती हैं, लेकिन नए अध्ययन से पता चला है कि अलग-अलग प्रकार की ये कोशिकाएं अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, जिस तरह पाचन तंत्र में मौजूद जटिल तंत्रिका नेटवर्क को अक्सर शरीर का 'दूसरा मस्तिष्क' कहा जाता है, उसी तरह हृदय के भीतर भी एक स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र मौजूद होता है। यह नेटवर्क हृदय के चारों ओर स्थित वसा ऊतक में फैला रहता है। इसकी तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क से आने वाले संकेतों को ग्रहण करने के साथ-साथ आपस में भी संदेशों का आदान-प्रदान करती हैं और अंततः हृदय की धड़कनों तथा उसकी कार्यप्रणाली को नियंत्रित करती हैं।

इन तंत्रिका कोशिकाओं को समझना अब तक मुश्किल क्यों था: हृदय के ऊतक में मौजूद कुल कोशिकाओं का केवल लगभग 0.01 प्रतिशत हिस्सा ही इन तंत्रिका कोशिकाओं का होता है। यही वजह है कि अब तक इनके वास्तविक कार्यों को समझना वैज्ञानिकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। इस समस्या को दूर करने के लिए शोधकर्ताओं ने आनुवंशिक रूप से संशोधित चूहों का उपयोग किया, जिससे हृदय की सभी तंत्रिका कोशिकाओं की स्पष्ट पहचान संभव हो सकी।

राष्ट्रपति रहते ट्रंप हुए ज्यादा अमीर: आखिर किन चीजों ने बढ़ाई दौलत कुल कितने अरब डॉलर पहुंची संपत्ति

वाशिंगटन, एजेंसी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वित्तीय लेनदेन और लगातार बढ़ती निजी संपत्ति एक बार फिर वैश्विक बहस का विषय बन गई है। सामने आई जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप की कुल संपत्ति में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। इस तेज उछाल के पीछे क्रिप्टोकरेंसी (डिजिटल मुद्रा) में निवेश और विदेशी बाजारों से हुई कमाई को प्रमुख वजह माना जा रहा है। फोर्ब्स की अरबपतियों की आधिकारिक सूची के अनुसार, वर्ष 2017 में डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति 3.5 अरब डॉलर (करीब 29,225 करोड़ रुपये) थी। वहीं, मार्च 2026 में जारी फोर्ब्स के ताजा मूल्यांकन के मुताबिक उनकी संपत्ति बढ़कर 6.5 अरब डॉलर (करीब 62,917.5 करोड़ रुपये) पहुंच गई। यानी छह वर्षों में उनकी

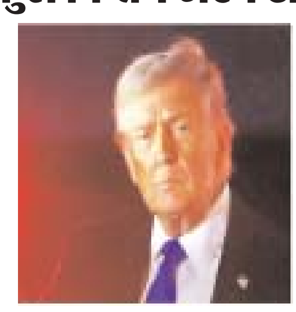

संपत्ति में लगभग तीन अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई।

क्रिप्टो कारोबार से कितनी हुई कमाई: जून 2026 में जारी ट्रंप की 927 पन्नों की अनिवार्य सरकारी वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने पिछले एक वर्ष में केवल क्रिप्टो से जुड़े कारोबार और निवेश के जरिए ही 1.4 अरब डॉलर से अधिक की आय अर्जित की। रिपोर्ट से यह संकेत मिलता है कि डिजिटल परिसंपत्तियों में उनके निवेश ने उनकी कुल संपत्ति बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

क्या राष्ट्रपति पद और कारोबारी हितों के टकराव पर उठे सवाल: रिपोर्ट में विस्तार से यह विश्लेषण किया गया है कि ट्रंप की संपत्ति में आई यह अप्रत्याशित बढ़ोतरी केवल बाजार की सामान्य तेजी और उनकी कारोबारी समझ का परिणाम है या फिर राष्ट्रपति के रूप में लिए गए फैसलों और सरकारी नीतियों का भी इसमें कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा है। इसी वजह से उनके वित्तीय हितों और संवैधानिक जिम्मेदारियों के बीच संभावित टकराव को लेकर बहस तेज हो गई है।

जनता की चिंता क्यों बढ़ रही है: रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद अमेरिका के साउथ जर्सी, कंबरलैंड और केप मे काउंटी समेत कई इलाकों के मतदाताओं ने इस मुद्दे पर चिंता जताई है। आलोचकों का कहना है ।

राष्ट्रपति मुर्मु की रोमानिया यात्रा से बदले समीकरण: एआई से ग्रीन एनर्जी तक साथ चलेंगे दोनों देश, सहयोग पर फोकस

बुखारेस्ट, एजेंसी। भारत और रोमानिया ने गुरुवार को आर्थिक सहयोग को अपनी द्विपक्षीय साझेदारी का अहम स्तंभ बताते हुए अगले तीन वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया। साथ ही दोनों देशों ने फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यह घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की रोमानिया यात्रा के दौरान हुई, जो पिछले तीन दशकों में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक यात्रा है।

क्या कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल और संस्कृति से जुड़े तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और रोमानिया के बीच सात दशकों से अधिक पुरानी मित्रता आपसी विश्वास, सम्मान और मजबूत

जन-से-जन संबंधों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि समय के साथ यह साझेदारी लगातार मजबूत हुई है और अब यह अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, गहरे सहयोग और साझा भविष्य की नई दिशा में आगे बढ़ रही है।

आर्थिक सहयोग को लेकर क्या बनी सहमति: राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि आर्थिक सहयोग दोनों देशों की साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) को मजबूत करेंगे और दोनों देशों के उद्योगों के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने बताया कि अगले तीन वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया है।

किन-किन क्षेत्रों में बढ़ेगा सहयोग: राष्ट्रपति ने बताया कि भारत और रोमानिया ने विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग), दवा उद्योग, स्वास्थ्य, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जैसे क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की पूरक क्षमताओं का लाभ उठाकर इस सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा।

रक्षा क्षेत्र में क्या हुआ फैसला: राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि रक्षा सहयोग भी भारत-रोमानिया संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों देशों ने नियमित आदान-प्रदान, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाकर इस साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है।

आईटीईसी और एआई प्रशिक्षण को लेकर क्या घोषणा हुई: उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने रोमानिया के लिए भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण अवसरों की संख्या दोगुनी करने का निर्णय लिया है। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से जुड़े पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय विदेश सेवा संस्थान ने रोमानियाई राजनयिकों को आगामी पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया है, जिसमें एआई और साइबर कूटनीति पर विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय मंचों पर किस सहयोग पर बनी सहमति: राष्ट्रपति मुर्मु ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) के तहत जारी सहयोग का स्वागत किया। उन्होंने यह भी कहा कि रोमानिया ने आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस से जुड़ने की इच्छा जताई है, जिसका भारत ने स्वागत किया है।

एसडीओपी कप-2026 का समापन, राजापुर और चाकघाट बने कबड्डी चैंपियन

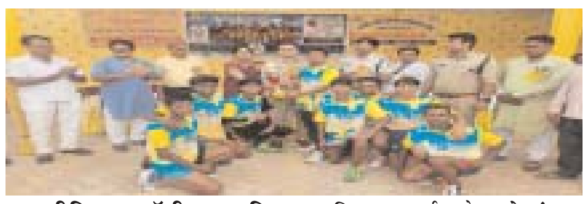

मीडिया ऑडीटर, रवि (निप्र)। युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देने और नशे से दूर रहने का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित दो दिवसीय एसडीओपी कप-2026 कबड्डी प्रतियोगिता का उत्साहपूर्ण समापन हुआ प्रतियोगिता का आयोजन समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीओपी त्योंथर मनस्वी शर्मा रहे, जबकि अध्यक्षता शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय त्योंथर की प्राचार्य डॉ. अंजना सिंह ने की। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास करते हैं तथा युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग के रोमांचक मुकाबले हुए बालक वर्ग में राजापुर टीम ने प्रथम, त्योंथर ने द्वितीय और सोहागी टीम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया वहीं बालिका वर्ग में चाकघाट टीम विजेता, त्योंथर टीम उपविजेता और मजगवां टीम तृतीय स्थान पर रही बालक वर्ग में बेस्ट रेडर का पुरस्कार करण कोल (राजापुर) और बेस्ट कैचर सचिन चौधरी (त्योंथर) को मिला बालिका वर्ग में शिवानी तिवारी को बेस्ट रेडर तथा दुर्गा माली को बेस्ट कैचर चुना गया समापन अवसर पर विजेता एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया गकार्यक्रम के अंत में राष्ट्रगान और 'खेलो कबड्डी-बनो चैंपियन, नशे से रहो दूर' संदेश के साथ प्रतियोगिता का समापन हुआ।

नीट पेपर लीक के विरोध में बैढ़न में सर्व समाज का प्रदर्शन, निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उठी मांग

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में शुक्रवार को सिंगरौली जिले के बैढ़न स्थित अंबेडकर चौक पर सर्व समाज द्वारा धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग की। प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष सहित कई पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरना स्थल पर मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और छात्रों के साथ हुए व्यवहार को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था

कि नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा देश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी हुई है ऐसी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है ताकि वास्तविक दोषियों की पहचान हो सके और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। धरना प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का मुद्दा भी उठाया गया। सर्व समाज के प्रतिनिधि बबलू सिंह ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई उचित नहीं थी उन्होंने इसे पुलिस की बर्बरता बताते हुए पूरे मामले की जांच कराने की मांग की उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मियों ने पहचान छिपाकर छात्रों पर बल प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने वाले विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी तय करने की मांग की सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग रखी क्षत्रिय कुलवंत संगठन के संयोजक अंकित सिंह ने कहा कि केवल जांच और कानून बनाने की घोषणाओं से विद्यार्थियों और आम लोगों का विश्वास वापस नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि दोषियों पर ठोस कार्रवाई हो और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं युवाओं के भविष्य का आधार होती हैं। यदि परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों के मनोबल पर पड़ता है इसलिए सरकार को इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए।

न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग: सामाजिक कार्यकर्ता सुषमा वर्मा ने कहा कि देश के छात्र केवल आश्वासन नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच और न्यायपूर्ण कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना आवश्यक है उन्होंने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी विद्यार्थी को ऐसी परेशानी का सामना न करना पड़े उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले में प्रभावी कदम उठाए जाएं और छात्रों को न्याय दिलाया जाए। उप्रदर्शन के दौरान सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात कही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नीट मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई, छात्रों के अधिकारों की रक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार समय की आवश्यकता है धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि पूरे मामले में पारदर्शी जांच कराकर दोषियों को सजा दी जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

रीवा खाद्य विभाग के JSO विनीत मिश्र के खिलाफ 4 सदस्यीय जांच दल गठित, आठ बिंदुओं पर होगी पड़ताल

समाजसेवी के अभ्यावेदन पर कार्रवाई, दुकानों में अनियमितता और विभागीय लापरवाही के आरोपों की होगी जांच

मीडिया ऑडीटर, रीवा(निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत रीवा जिले में खाद्य विभाग में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी (JSO) विनीत मिश्र के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई मामले की जांच के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की अध्यक्षता में चार सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है जानकारी के अनुसार समाजसेवी कमल सिंह बघेल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में लगाए गए आठ बिंदुओं पर

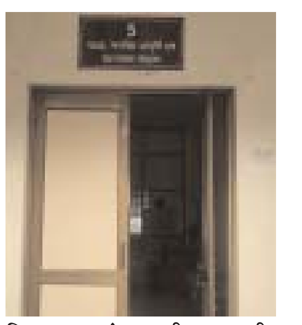

विस्तृत जांच की जाएगी। अभ्यावेदन में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के संचालन और विभागीय कार्यप्रणाली से जुड़े आरोप लगाए गए थे। अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि खाद्य विभाग के अधिकारी द्वारा जिले की कई शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालकों से अनैतिक लाभ लेकर स्टॉक में बदलाव किया गया आरोप है कि कुछ दुकानों के खाद्यान्न स्टॉक को संचालकों की सुविधा के अनुसार घटाया-बढ़ाया गया। इसके अलावा कुछ उपार्जन समितियों और शासकीय उचित मूल्य दुकानों में अनियमितताएं पाए जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज कराने और वसूली जैसी कार्रवाई नहीं किए जाने का भी आरोप लगाया गया है शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे शासन को आर्थिक क्षति पहुंची अभ्यावेदन में इन आरोपों के अलावा छह अन्य बिंदुओं पर भी जांच की मांग की गई थी मामले में करीब आठ माह पूर्व अपर मुख्य सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को शिकायत प्रस्तुत की गई थी इसके बाद अपर कलेक्टर रीवा को जांच के निर्देश दिए गए थे। शिकायत की जांच निर्धारित समय सीमा में पूरी नहीं होने के कारण तत्कालीन कलेक्टर मती प्रतिभा पाल द्वारा जांच की जिम्मेदारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा को सौंप दी गई थी अब इसी आधार पर चार सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया है। जांच दल शिकायत में उल्लेखित सभी आठ बिंदुओं की तथ्यात्मक जांच करेगा और संबंधित दस्तावेजों, रिकॉर्ड तथा विभागीय कार्यप्रणाली का परीक्षण करेगा जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

विधानसभा में भी उठा था मामला: यह मामला मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में भी उठा था। सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में इस मुद्दे को उठाते हुए मामले के शीघ्र निराकरण की मांग की थी। विधायक द्वारा मामला उठाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लिया और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार जांच पूरी होने के बाद यदि आरोप प्रमाणित पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

टिकैतन पुरवा में सरपंच-ठेकेदार की मिलीभगत का आरोप, ग्रामीणों ने तकनीकी जांच और कार्रवाई की मांग की

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा जिले के जनपद पंचायत जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकैतन पुरवा में निर्माणाधीन स्टॉप डैम को लेकर ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य में निर्धारित मापदंडों और तकनीकी मानकों की अनदेखी की जा रही है, जिससे इसकी गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं ग्रामीणों के अनुसार स्टॉप डैम निर्माण कार्य में सरपंच और ठेकेदार की कथित मिलीभगत के चलते नियमों का पालन नहीं किया जा रहा आरोप है कि सरकारी राशि से किए जा रहे इस निर्माण में लापरवाही बरती जा रही है जिससे भविष्य में डैम की मजबूती प्रभावित हो सकती है। स्थल निरीक्षण के दौरान स्टॉप डैम के आसपास मिट्टी का कटाव, अधूरा समतलीकरण और निर्माण कार्य की गुणवत्ता से जुड़े कई बिंदु सामने आने की बात ग्रामीणों ने कही है। उनका आरोप है कि निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री और कार्य की प्रक्रिया की तकनीकी जांच

आवश्यक है ग्रामीणों का कहना है कि स्टॉप डैम का निर्माण क्षेत्र में जल संरक्षण और किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ तो बारिश के बाद संरचना को नुकसान पहुंच सकता है और योजना का वास्तविक लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाएगा।

ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि निर्माण स्थल की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता, उपयोग की गई सामग्री और कार्य में लगे जिम्मेदारों की भूमिका की जांच कर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने कहा कि जल संरक्षण से जुड़ी योजनाएं सीधे किसानों और ग्रामीणों के हित से जुड़ी होती हैं ऐसे में निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना जरूरी है ताकि सरकारी धन का सही उपयोग हो सके और क्षेत्र के लोगों को इसका स्थायी लाभ मिल सके प्रशासन द्वारा जांच कराए जाने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

स्थानांतरण आदेश के बाद भी 13 साल से पदस्थ शिक्षक नहीं हुए रिलीव, गेदुरहा आश्रम में आदेश की अनदेखी के आरोप

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा जिले के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत अनु. जनजाति बालक आश्रम गेदुरहा में पदस्थ एक शिक्षक के स्थानांतरण आदेश के बाद भी उन्हें रिलीव नहीं किए जाने का मामला सामने आया है आरोप है कि शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के बावजूद विभागीय अधिकारी कर्मचारी उसका पालन नहीं कर रहे हैं जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार कार्यालय कलेक्टर (अनु. जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग) जिला रीवा द्वारा 16 जून 2026 को स्थानांतरण आदेश जारी किया गया था यह आदेश मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक GAD/4/0001/2026-GAD-9-01 दिनांक 22 मई 2026 तथा कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक शिक्षा स्था. 20261/1064163/2026 दिनांक 3 जून 2026 के निर्देशों के आधार पर जारी किया गया। स्थानांतरण नीति की कंडिका 12 के अनुसार प्रशासनिक अथवा स्वैच्छिक स्थानांतरण के तहत जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना स्थल पर आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है इसी आदेश के तहत अनु. जनजाति बालक आश्रम गेदुरहा में पदस्थ शिक्षक विंधेश्वरी वर्मा का स्थानांतरण गेदुरहा से अनु. जाति सीनियर बालक छात्रावास मझियार के लिए किया गया बताया जा रहा है कि शिक्षक यहां करीब 13 वर्षों से पदस्थ हैं लेकिन स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद भी उन्हें वर्तमान संस्था से कार्यमुक्त (रिलीव) नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिक्षक गेदुरहा से जाना नहीं चाहते हैं, जिसके चलते विभागीय स्तर पर उन्हें रिलीव करने में देरी की जा रही है वहीं कुछ लोगों ने अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई है मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जब शासन स्तर से स्थानांतरण आदेश जारी हो चुका है तो फिर संबंधित कर्मचारी को नवीन पदस्थापना स्थल पर भेजने में देरी क्यों की जा रही क्या विभागीय अधिकारी शासन के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर किसी दबाव के चलते कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कलेक्टर ने हनुमना के नवनिर्मित तहसील भवन का किया निरीक्षण, गुणवत्ता और सुविधाओं पर दिए निर्देश

मीडिया ऑडीटर, रीवा (निप्र)। रीवा जिले के हनुमना तहसील में नवनिर्मित तहसील भवन का कलेक्टर संजय कुमार जैन ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भवन निर्माण की गुणवत्ता, कार्यालयीन व्यवस्थाओं और आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए शेष कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए कलेक्टर जैन ने तहसील भवन के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण करते हुए राजस्व अभिलेख कक्ष, न्यायालय कक्ष, कार्यालयीन कक्ष, प्रतीक्षालय सहित परिसर की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया उन्होंने भवन में उपलब्ध पेयजल, विद्युत व्यवस्था, स्वच्छता, शौचालय और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि शासकीय भवनों का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप होना चाहिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन का प्रत्येक कार्य गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित तरीके से पूरा कराया जाए ताकि लंबे समय तक नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें उन्होंने निर्माण एजेंसी से कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए शेष निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए साथ ही भवन में यदि किसी प्रकार की कमी या आवश्यकता सामने आती है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर करने को कहा कलेक्टर ने कहा कि तहसील कार्यालय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण और आमजन अपने राजस्व संबंधी कार्यों के लिए पहुंचते हैं ऐसे में कार्यालय परिसर में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालयीन व्यवस्थाएं व्यवस्थित रहें और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

सदगुरु कृपा के अवतरण का महापर्व गुरुपूर्णिमा महोत्सव 26 जुलाई को

सिद्ध नरसिंह मंदिर में होगा भव्य आयोजन, जगतगुरु रामानुजाचार्य मद् महाराज के सानिध्य में श्रद्धालु करेंगे गुरु चरण पादुका पूजन

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सद्गुरु की कृपा, आध्यात्मिक चेतना और गुरु-शिष्य परंपरा के पावन उत्सव गुरुपूर्णिमा महोत्सव का आयोजन रविवार 26 जुलाई को सिद्ध नरसिंह मंदिर अमरपाटन में किया जाएगा। रामजानकी शक्तिपीठ पुरानीलंका चित्रकूट पीठाधीश्वर रामानुजाचार्य मद् जगतगुरु जी महाराज के सानिध्य में आयोजित होने वाले इस महापर्व में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है गुरुपूर्णिमा महोत्सव का शुभारंभ रविवार सुबह 8 बजे से होगा। इस अवसर पर श्रद्धालु सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा, भक्ति और समर्पण भाव के

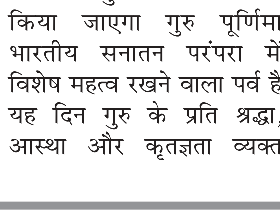

साथ पूजा-अर्चना करेंगे। आयोजन में गुरु चरण पादुका पूजन, आध्यात्मिक प्रवचन एवं धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा गुरु पूर्णिमा भारतीय सनातन परंपरा में विशेष महत्व रखने वाला पर्व है यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, आस्था और कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है शास्त्रों में गुरु को जीवन के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश देने वाला मार्गदर्शक बताया गया गुरु के आशीर्वाद से ही साधक को आध्यात्मिक उन्नति और परम सत्य की अनुभूति का मार्ग प्राप्त होता है आयोजन से जुड़े भक्तों ने बताया कि जीव को अनेक जन्मों के संचित पुण्यों के फलस्वरूप मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और इसके बाद यदि उसे सद्गुरु के चरणों की शरण मिल जाए तो उसका जीवन सफल और धन्य हो जाता है सद्गुरु की कृपा से ही मनुष्य को संसार की अस्थिरता और नश्वरता का बोध होता है तथा परमात्मा के चरणों में प्रेम और भक्ति की भावना जागृत होती है उन्होंने कहा कि गुरु कृपा से जब साधक के हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम की ज्योति प्रज्वलित होती है तो उसका अंतर्मन प्रकाशमय हो जाता है उसके विचार, व्यवहार और वाणी में सकारात्मकता और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है इसी भाव को लेकर गुरुपूर्णिमा महोत्सव को सद्गुरु कृपा के अवतरण का महापर्व माना जाता है पुरानीलंका भक्त मंडल के संयोजक राजगुरु मनोज अग्निहोत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु सानिध्य में विभिन्न स्थानों पर भी गुरुपूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा उन्होंने बताया कि 29 जुलाई बुधवार को मोहनराम मंदिर शहडोल में गुरु सानिध्य में विशेष महोत्सव आयोजित होगा। इसके साथ ही इसी अवसर पर पुरानीलंका आश्रम चित्रकूट, रामजानकी कृपाधाम वृंदावन, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, जगन्नाथपुरी उड़ीसा एवं मैहर स्थित धार्मिक स्थलों में भी गुरुपूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा भक्त परिवार अपनी सुविधानुसार इन स्थानों पर पहुंचकर गुरु चरण पादुका पूजन कर सकेंगे और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में सहभागी बन सकेंगे। आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर गुरुपूर्णिमा महोत्सव में भाग लें और सद्गुरु के आशीर्वाद का लाभ प्राप्त करें आयोजकों के अनुसार यह आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन में सदाचार, भक्ति, सेवा और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने का अवसर भी है।

खनन प्रभावित गांवों में पहली बार विशेष स्वास्थ्य शिविर, 18 विशेषज्ञ डॉक्टर करेंगे ग्रामीणों की जांच

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले के खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच और उपचार के लिए जिला प्रशासन ने विशेष पहल शुरू की है। खनन गतिविधियों से प्रभावित गांवों में लोगों को होने वाली संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए शनिवार को चार गांवों में एक साथ विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा इन शिविरों में 18 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण करेगी और आवश्यकतानुसार उपचार एवं चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराएगी कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर आयोजित होने वाले इन स्वास्थ्य शिविरों का उद्देश्य खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन करना, संभावित बीमारियों की पहचान करना और प्रभावित लोगों को समय पर उपचार उपलब्ध कराना है प्रशासन का मानना है कि खनन क्षेत्रों में लंबे समय तक रहने वाले ग्रामीणों को धूल, प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को जिले के चार खनन प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें बघवार, बघौड़ी, अमहा और हर्दी गांव शामिल हैं। सभी स्थानों पर शिविर का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है इन शिविरों के सफल संचालन के लिए चार अलग-अलग चिकित्सा दल गठित किए गए हैं। प्रत्येक दल में विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, ताकि ग्रामीणों को एक ही स्थान पर अलग-अलग बीमारियों से संबंधित जांच और उपचार की सुविधा मिल सके।

गतिरोध की राजनीति

संपादकीय

यह शुभ संकेत नहीं कि 2024 के नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपित के खि प्रधानमंत्री मोदी ने पेपर लीक से जुड़े मामलों के आरोपितों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाने की घोषणा की, वह उन्हें बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। अच्छा होता कि इस विषय पर वे समय रहते देश को सीधे तौर पर संबोधित करते। इससे लोगों और खासकर छात्रों के इस भरोसे को बल मिलता कि सरकार इस मामले के दोषियों को शीघ्र सजा दिलाने के प्रति सचमुच प्रतिबद्ध है।

जैसे नीट मामले में प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर वक्तव्य आने में देरी हुई, वैसे ही इस प्रकरण को लेकर धरने पर बैठे समूह कांकरोच जनता पार्टी से संपर्क-संवाद करने में भी। इसका परिणाम यह हुआ कि न केवल सीजेपी के संसद मार्च में हिंसा हुई, बल्कि राजनीतिक रोटियां सेंकने वालों को भी मौका मिल गया। इसके पहले मौका उन्हें भी मिला, जो सीजेपी के संसद मार्च में शामिल होकर अराजकता फैलाने का इरादा रखते थे। वे अपने इरादे में इसलिए सफल रहे, क्योंकि पुलिस न तो भीड़ का अनुमान लगा सकी और न ही उसकी उग्रता का। पुलिस के पास शायद अचानक उमड़ी और संसद भवन जाने को उतावली भीड़ से निपटने की कोई ठोस रणनीति या तैयारी नहीं थी। इसके अभाव में ही उसे सख्ती का सहारा लेना पड़ा, जो स्वाभाविक रूप से एक मुद्दा बन गई है। विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता और इसीलिए उसने यह मांग रख दी है कि संसद तब चलेगी, जब पुलिस की सख्ती पर प्रधानमंत्री माफी मांगने के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से त्यागपत्र लेंगे। विपक्षी दलों जैसा रवैया सीजेपी ने भी अपना लिया है। वह अपनी शर्तों के साथ-साथ अपने बताए ठिकाने पर सरकार से बात करने पर अड़ गई है। अब उसके लोग किसी मंत्री के घर या दफ्तर बात करने के लिए तैयार नहीं। यह हठधर्मिता है। इससे विचित्र और कुछ नहीं हो सकता कि गतिरोध इस पर कायम हो जाए कि बात कहां होनी चाहिए? कहना कठिन है कि उसके और सरकार के बीच का गतिरोध कैसे टूटेगा? लगता है जैसे विपक्ष की दिलचस्पी संसद चलने देने में नहीं, वैसे ही सीजेपी की भी पहली प्राथमिकता परीक्षा व्यवस्था में सुधार की नहीं दिखती। उसका एकमात्र उद्देश्य शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र दिखता है। इस हिसाब से तो उन सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के त्यागपत्र मांगे जाने चाहिए, जहां पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक हुए हैं।

छात्र हित के नाम पर की जा रही इस राजनीति के बीच सरकार को यह सचमुच सुनिश्चित करना चाहिए कि पेपर लीक के दोषियों को सच में समय पर कठोर दंड मिले। इसके लिए सीबीआई को भी तत्परता दिखानी होगी। यह शुभ संकेत नहीं कि 2024 के नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपित के खिलाफ सीबीआई को कोई प्रमाण नहीं मिले।

अब आगे क्या? इस्तीफ़ा या पेपर लीक पर संसद में बहस

सौरभ वार्ष्णेय

देश की संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जहां जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर चर्चा, जवाबदेही और समाधान की अपेक्षा की जाती है। लेकिन मानसून सत्र के शुरुआती तीन दिन जिस प्रकार लगातार हंगामे और स्थगन की भेंट चढ़े हैं, उसने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या संसद जनहित के मुद्दों के समाधान का मंच बनेगी या केवल राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बनकर रह जाएगी? वर्तमान गतिरोध का सबसे बड़ा कारण देशभर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक की घटनाएं हैं। इन घटनाओं ने लाखों छात्रों के भविष्य, उनकी वर्षों की मेहनत और पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। विपक्ष इस मुद्दे को केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का विषय मानते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े की मांग पर अड़ा हुआ है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वह इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा कराने के लिए तैयार है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मंत्री का इस्तीफ़ा केवल राजनीतिक दबाव का परिणाम नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी जिम्मेदारी तय होने और नैतिक उत्तरदायित्व के आधार पर होना चाहिए। वहीं विपक्ष का यह तर्क भी पूरी तरह निराधार नहीं कहा जा सकता कि जब सरकार उपलब्धियों का श्रेय स्वयं लेती है, तो गंभीर प्रशासनिक विफलताओं की नैतिक जिम्मेदारी भी उसे स्वीकार करनी चाहिए। यही कारण है कि इस्तीफ़े की मांग राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। दूसरी ओर यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि संसद में इस पूरे प्रकरण पर गंभीर, तथ्यात्मक और व्यापक चर्चा हो। केवल नारेबाज़ी या सदन को बाधित करने से न तो छात्रों का भविष्य सुरक्षित होगा और न ही परीक्षा प्रणाली में सुधार आएगा। देश यह जानना चाहता है कि आखिर बार-बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्था में चूक कहां है? कौन-से संगठित गिरोह इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं? अब तक कितनों पर कार्रवाई हुई? भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की ठोस रणनीति क्या है? संसद में यदि इन सभी प्रश्नों पर विस्तृत बहस होती है तो यह लोकतंत्र और छात्रों—दोनों के हित में होगा। बहस से जवाबदेही भी तय होगी और सुधार की दिशा भी स्पष्ट होगी। लेकिन यदि बहस से पहले केवल इस्तीफ़े की मांग और सरकार की ओर से केवल राजनीतिक प्रतिरोध चलता रहा, तो सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों युवाओं का होगा, जिनका भविष्य इस पूरे विवाद के बीच अधर में लटका हुआ है। इस बीच राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों का आंदोलन लगातार व्यापक होता दिखाई दे रहा है। विभिन्न राज्यों से छात्र वहां पहुंच रहे हैं और निष्पक्ष जांच, दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई तथा परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। कुछ समय पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को उनके आंदोलन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद यह माना जा रहा था कि विरोध प्रदर्शनों की धार कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन वर्तमान छात्र आंदोलन यह संकेत देता है कि युवाओं का आक्रोश केवल किसी एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था के प्रति गहराते अविश्वास का प्रतीक बन चुका है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह पेपर लीक पर संसद में चर्चा करने और आंदोलनरत छात्रों से संवाद के लिए भी तैयार है। यदि ऐसा है, तो यह स्वागतयोग्य पहल हो सकती है। लोकतंत्र में संवाद ही किसी भी संकट का सबसे प्रभावी समाधान माना जाता है। लेकिन संवाद तभी सार्थक होगा जब उसके साथ ठोस निर्णय, समयबद्ध कार्रवाई और पारदर्शिता भी जुड़ी हो। आज देश का छात्र केवल न्याय नहीं, बल्कि भरोसा मांग रहा है। वह यह विश्वास चाहता है कि उसकी वर्षों की मेहनत कुछ लोगों के भ्रष्टाचार और लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ेगी। यह केवल एक परीक्षा का प्रश्न नहीं, बल्कि देश की प्रतिभा, शिक्षा व्यवस्था और भविष्य की विश्वसनीयता का प्रश्न है। सरकार और विपक्ष—दोनों की जिम्मेदारी है कि वे इस संवेदनशील विषय को राजनीतिक लाभ-हानि के चश्मे से देखने के बजाय राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से देखें। यदि शिक्षा मंत्री के इस्तीफ़े से जवाबदेही तय होती है तो उस पर भी विचार होना चाहिए, और यदि संसद में गंभीर बहस से बेहतर समाधान निकल सकता है तो उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दोनों विकल्प एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक जवाबदेही की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं।

सवालों से घिरा लोकतंत्र, सड़कों पर युवा

कुमार कृष्णन

लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना यह नहीं होती कि सत्ता बहुत शक्तिशाली हो जाती है; वह तब पैदा होती है, जब समाज प्रश्न पूछना छोड़ देता है। नागरिकों की चुप्पी, विश्वविद्यालयों का मौन और युवाओं का केवल निजी सफलता तक सीमित हो जाना किसी भी लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं होता। इसके विपरीत, जब युवा व्यवस्था से जवाब मांगते हैं, तब वह केवल विरोध नहीं होता; वह लोकतंत्र की आत्मा के भीतर उठती नई हलचल का संकेत होता है। देश में शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और रोजगार के प्रश्नों को लेकर उभरे छात्र-युवा आंदोलन को इसी व्यापक संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। इसे केवल किसी एक परीक्षा, किसी एक पेपर लीक या किसी एक मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित कर देना उसकी प्रकृति को छोटा कर देना होगा। यह उस पीढ़ी की बेचैनी है जिसने वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, रोजगार की अनिश्चितता झेली और अब अपनी मेहनत से अधिक व्यवस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के लिए विवश हो रही है। दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ आंदोलन कुछ ही दिनों में अनेक राज्यों तक फैल गया। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद हुई पुलिस कार्रवाई ने इस बहस को राष्ट्रीय विमर्श का विषय बना दिया। लाठीचार्ज, आँसू गैस, घायल छात्र और तनावपूर्ण हालात ने एक मूलभूत प्रश्न सामने रखा—क्या लोकतंत्र में असहमति का पहला उत्तर पुलिस बल होना चाहिए, या संवाद का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए? निस्संदेह, कानून-व्यवस्था बनाए रखना किसी भी सरकार का दायित्व है। यदि हिंसा होती है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचता है तो प्रशासन हस्तक्षेप करेगा ही। लेकिन लोकतंत्र की परिपक्वता का आकलन केवल इस बात से नहीं होता कि उसने कानून कैसे लागू किया; उससे भी अधिक इस बात से होता है कि उसने असंतोष को समय रहते सुना या नहीं। संवाद की विफलता अक्सर टकराव का पहला कारण बनती है। इस आंदोलन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि उसने नई पीढ़ी को लेकर बनी कई रूढ़ धारणाओं को तोड़ दिया है। लंबे समय से कहा जाता रहा कि आज का युवा केवल मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और निजी करियर तक सीमित है। लेकिन जंतर-मंतर, पटना और देश के अनेक शहरों में दिखाई देने वाली भीड़ ने इस धारणा को चुनौती दी। हजारों छात्र-छात्राएँ अपनी पढ़ाई, नौकरी और निजी सुविधाएँ छोड़कर सड़कों पर उतरे। बड़ी संख्या में युवतियों की सक्रिय भागीदारी ने इस आंदोलन को और अधिक अर्थपूर्ण बना दिया। अनेक युवतियों ने कहा कि आंदोलन के बीच उन्हें बराबरी, सम्मान और सुरक्षा का अनुभव हुआ। किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की नैतिक शक्ति का इससे बड़ा प्रमाण शायद ही हो। यह मान लेना भी भूल होगी कि यह असंतोष अचानक पैदा हुआ है। इसकी पृष्ठभूमि वर्षों से तैयार हो रही थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर उठते सवाल, भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार विलंब, बेरोज़गारी का दबाव, शिक्षा की बढ़ती लागत और भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना—इन सबने मिलकर युवाओं के भीतर गहरा अविश्वास पैदा किया है। जब किसी समाज का परिश्रमी युवा अपनी प्रतिभा से अधिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगे, तब यह केवल प्रशासनिक समस्या नहीं रहती; यह लोकतांत्रिक संस्थाओं में भरोसे का संकट बन जाती है। पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति का बड़ा हिस्सा धार्मिक, सांस्कृतिक और पहचान आधारित मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमता रहा है। इन विषयों का अपना महत्व है, लेकिन इसी दौरान शिक्षा, विश्वविद्यालयों, शोध, रोजगार और सार्वजनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता जैसे प्रश्न धीरे-धीरे सार्वजनिक बहस के हाशिए पर चले गए। वर्तमान छात्र आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान शायद यही है कि उसने राष्ट्रीय विमर्श को फिर उन प्रश्नों की ओर मोड़ दिया है, जिनका सीधा संबंध करोड़ों युवाओं के भविष्य से है। इतिहास बताता है कि जब भी युवाओं ने अपने समय के बुनियादी प्रश्नों को लेकर आवाज़ उठाई है, तब राजनीति को अपनी भाषा बदलनी पड़ी है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में युवाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष को निर्णायक गति दी। 1974 के छात्र आंदोलन ने लोकतंत्र और जवाबदेही की बहस को नई दिशा दी। मंडल आंदोलन ने सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय विमर्श का केंद्रीय प्रश्न बनाया। हर दौर का अपना एजेंडा था, लेकिन एक बात समान रही—युवाओं ने राजनीति को उसकी सुविधाजनक सीमाओं से बाहर निकलने के लिए बाध्य किया। आज का प्रश्न शिक्षा, रोजगार और अवसरों की निष्पक्षता का है। संभव है कि आने वाले वर्षों में यही प्रश्न भारतीय राजनीति की दिशा भी तय करें। युवा आंदोलनों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे केवल तात्कालिक घटनाओं की प्रतिक्रिया नहीं होते, बल्कि व्यवस्था के भीतर लंबे समय से जमा असंतोष का सार्वजनिक विस्फोट होते हैं। आज शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और रोजगार के प्रश्न पर उभरे छात्र-युवा आंदोलन को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है। इसे केवल किसी एक परीक्षा, किसी एक पेपर लीक या किसी एक मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित करके समझना भूल होगी। यह उस पीढ़ी की सामूहिक व्यथा है, जिसने वर्षों तक कठिन परिश्रम किया, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, बेरोज़गारी का दबाव झेला और अब अपनी मेहनत की निष्पक्षता पर ही सवाल खड़े होते देख रही है। दिल्ली के जंतर-मंतर से शुरू हुआ यह आंदोलन कुछ ही दिनों में कई राज्यों तक फैल गया। बिहार की राजधानी पटना में छात्रों के प्रदर्शन और उसके बाद पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच हुए टकराव ने इस बहस को और तीखा बना दिया। लाठीचार्ज, पथराव, आँसू गैस और घायल छात्रों की तस्वीरों ने पूरे देश के सामने एक बुनियादी प्रश्न रख दिया—क्या लोकतंत्र में असहमति का उत्तर केवल पुलिस बल है, या संवाद की परंपरा अभी भी जीवित है? लोकतांत्रिक शासन में कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का दायित्व है। यदि हिंसा होती है या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचता है तो प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ता है।

लेकिन इससे पहले यह पूछना भी उतना ही आवश्यक है कि क्या संवाद के सभी रास्ते समाप्त हो चुके थे? क्या छात्रों की आशंकाओं और मांगों को समय रहते गंभीरता से सुना गया? लोकतंत्र की सफलता केवल व्यवस्था बनाए रखने में नहीं, बल्कि असंतोष को हिंसा में बदलने से पहले उसे संवाद में बदल देने की क्षमता में निहित होती है। इस आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसने उस धारणा को चुनौती दी है जिसके अनुसार नई पीढ़ी केवल मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और निजी करियर तक सीमित हो चुकी है। जंतर-मंतर से लेकर पटना, भागलपुर, मुंगेर,लखनऊ, जयपुर, भोपाल और दूसरे शहरों तक दिखाई देने वाली भीड़ ने साबित किया कि यह पीढ़ी केवल डिजिटल नागरिक नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक नागरिक भी है। हजारों छात्र-छात्राएँ अपनी कक्षाएँ छोड़कर, नौकरी से अवकाश लेकर और कई मामलों में पारिवारिक असहमति के बावजूद सड़कों पर उतरे। बड़ी संख्या में युवतियों की भागीदारी ने इस आंदोलन को एक नया सामाजिक आयाम दिया। अनेक युवतियों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि आंदोलन के बीच उन्हें बराबरी, सम्मान और सुरक्षा का अनुभव हुआ। किसी भी जनांदोलन के लिए इससे बड़ी सामाजिक पूँजी शायद ही कोई दूसरी हो सकती है। यह मान लेना भी भूल होगी कि यह आक्रोश अचानक पैदा हुआ है। इसकी जड़ें पिछले कई वर्षों में विकसित हुई परिस्थितियों में हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं पर बार-बार उठते प्रश्न, भर्ती प्रक्रियाओं में लंबा विलंब, बेरोज़गारी का बढ़ता दबाव, शिक्षा का महँगा होना और अवसरों की असमानता—इन सबने मिलकर युवाओं के भीतर गहरा अविश्वास पैदा किया है। जब किसी समाज में मेहनत करने वाले युवा अपनी योग्यता से अधिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगें, तो यह केवल प्रशासनिक संकट नहीं रह जाता; यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति भरोसे का संकट बन जाता है। भारतीय राजनीति का बड़ा हिस्सा पिछले एक दशक में सांस्कृतिक और पहचान-आधारित प्रश्नों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा है। इन विषयों का अपना महत्व है, लेकिन इसी दौरान शिक्षा, विश्वविद्यालयों, शोध, रोजगार और सार्वजनिक संस्थाओं की विश्वसनीयता जैसे मुद्दे अक्सर हाशिए पर चले गए। वर्तमान आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व यही है कि उसने राष्ट्रीय बहस को फिर उन बुनियादी प्रश्नों की ओर मोड़ दिया है जिनका संबंध सीधे करोड़ों युवाओं के भविष्य से है। इतिहास बताता है कि जब भी युवा अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, तब राजनीति की भाषा बदलनी पड़ती है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में युवाओं ने स्वतंत्रता संघर्ष को निर्णायक गति दी थी। 1974 के छात्र आंदोलन ने लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रश्न राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया। मंडल आंदोलन ने सामाजिक न्याय की बहस को नई दिशा दी। आज की पीढ़ी शिक्षा, रोजगार, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और संस्थागत विश्वसनीयता की बात कर रही है। हर दौर का अपना एजेंडा रहा है, लेकिन एक बात समान रही—जब युवाओं ने बोलना शुरू किया, तब राजनीति को अपनी प्राथमिकताएँ बदलनी पड़ीं। हर जनांदोलन अपने साथ एक राजनीतिक संदेश अवश्य लाता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उसका नैतिक संदेश होता है। वर्तमान छात्र-युवा आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लोकतंत्र में जवाबदेही केवल चुनावों से तय नहीं होती। सरकारें बहुमत से बनती हैं, लेकिन उनका नैतिक बल जनता के विश्वास से आता है। जब युवा अपनी मेहनत, अपने भविष्य और संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाते हैं, तब उन प्रश्नों को केवल राजनीतिक विरोध मानकर टाल देना पर्याप्त नहीं होता।

यही कारण है कि यह आंदोलन अब केवल छात्रों का आंदोलन नहीं रह गया है। यह उस व्यापक चिंता का प्रतीक बनता जा रहा है जिसमें अभिभावक, शिक्षक, शिक्षाविद् और समाज का बड़ा वर्ग भी अपने भविष्य की झलक देख रहा है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र का भविष्य उसकी संसदों से पहले उसके विश्वविद्यालयों और उसके युवाओं में लिखा जाता है। यदि वहाँ भरोसा कमजोर होगा, तो लोकतंत्र की नींव भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ने लगेगी। हर बड़ा जनांदोलन अपने समय से एक कठिन प्रश्न पूछता है। आज का छात्र-युवा आंदोलन भी वही कर रहा है। उसका सबसे बड़ा प्रश्न केवल इतना नहीं है कि किसी परीक्षा में गड़बड़ी क्यों हुई या किसी मंत्री को पद पर बने रहना चाहिए या नहीं। उसका वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएँ युवाओं के विश्वास के अनुरूप स्वयं को बदलने के लिए तैयार हैं? भारतीय लोकतंत्र का इतिहास बताता है कि हर दौर में युवाओं ने केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि विचार परिवर्तन की भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता आंदोलन में छात्रों ने अंग्रेज़ी शासन को चुनौती दी। 1974 के छात्र आंदोलन ने लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रश्न उठाया। मंडल आंदोलन ने सामाजिक न्याय की बहस को नई दिशा दी। आज की पीढ़ी शिक्षा, रोजगार, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और संस्थागत विश्वसनीयता की बात कर रही है। हर दौर का अपना एजेंडा रहा है, लेकिन एक बात समान रही—जब युवाओं ने बोलना शुरू किया, तब राजनीति को अपनी प्राथमिकताएँ बदलनी पड़ीं। आज का आंदोलन भी इसी कसौटी पर परखा जाएगा। इसका मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होगा कि किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया या नहीं, कितनी गिरफ्तारियाँ हुईं या कितने प्रदर्शन हुए। असली प्रश्न यह होगा कि क्या इससे शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनी? क्या प्रतियोगी परीक्षाओं पर युवाओं का भरोसा लौटा? क्या भर्ती प्रक्रियाएँ अधिक विश्वसनीय हुईं? क्या विश्वविद्यालयों में संवाद का वातावरण मजबूत हुआ? और क्या सरकार तथा राजनीतिक दलों ने युवाओं की आकांक्षाओं को गंभीरता से सुना? यह भी उतना ही आवश्यक है कि आंदोलन अपनी नैतिक शक्ति बनाए रखे। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी वैचारिक स्पष्टता, अनुशासन और अहिंसक चरित्र में होती है। हिंसा किसी भी आंदोलन की नैतिक विश्वसनीयता को कमजोर करती है। उसी प्रकार राज्य की वैधता भी केवल कानून लागू करने से नहीं, बल्कि नागरिकों का विश्वास अर्जित करने से बनती है। सरकार की जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की नहीं, बल्कि विश्वास बहाल करने की भी होती है। विपक्ष के सामने भी कम चुनौती नहीं है। यदि वह इस आंदोलन को केवल राजनीतिक अवसर के रूप में देखेगा, तो युवाओं की अपेक्षाओं को समझने में चूक जाएगा। आज का युवा केवल भाषण नहीं सुनना चाहता; वह नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही चाहता है। उसके लिए रोजगार किसी विचारधारा का नहीं, जीवन का प्रश्न है। शिक्षा किसी राजनीतिक नारे का नहीं, उसके भविष्य का आधार है। इसलिए जो भी राजनीतिक शक्ति युवाओं का विश्वास जीतना चाहती है, उसे केवल विरोध नहीं, बल्कि विश्वसनीय विकल्प भी प्रस्तुत करना होगा। इस आंदोलन ने एक और मिथक तोड़ा है कि नई पीढ़ी सार्वजनिक जीवन से कट चुकी है। वास्तव में यह पीढ़ी तकनीक का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि संगठन, संवाद और जनमत निर्माण के लिए भी कर रही है। वह सवाल पूछ रही है, तर्क दे रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अपनी भागीदारी दर्ज करा रही है। यह किसी भी जीवंत लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है।

आज आवश्यकता केवल किसी एक प्रशासनिक निर्णय की नहीं, बल्कि व्यापक शिक्षा सुधार की है। परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, समयबद्ध नियुक्तियाँ, विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक स्वायत्तता, शोध की गुणवत्ता और समान अवसर—इन प्रश्नों को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो असंतोष बार-बार नए रूपों में सामने आएगा। लेकिन यदि इन मुद्दों पर गंभीर सुधार की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वर्तमान आंदोलन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक मोड़ सिद्ध हो सकता है। लोकतंत्र की शक्ति केवल चुनाव जीतने में नहीं होती; उसकी असली ताकत अपने नागरिकों की आवाज़ सुनने में होती है। विशेषकर तब, जब वह आवाज़ देश के युवाओं की हो। क्योंकि युवा केवल आज के मतदाता नहीं हैं, वे कल के नागरिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासक और नीति-निर्माता भी हैं। उनके भीतर पैदा होने वाला विश्वास या अविश्वास अंततः राष्ट्र की दिशा तय करता है। भारत आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। निर्णय केवल सरकार को नहीं, पूरे राजनीतिक वर्ग और समाज को लेना है। क्या हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाएँगे, जिसमें प्रतिभा पर भरोसा हो? क्या हम ऐसा लोकतंत्र विकसित करेंगे, जहाँ असहमति को राष्ट्र-विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र की स्वाभाविक और आवश्यक अभिव्यक्ति माना जाए? क्या हम अपने युवाओं को केवल चुनावी आँकड़ों के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे? इन प्रश्नों के उत्तर आने वाले वर्षों की राजनीति और शासन की दिशा तय करेंगे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस समय देश की सबसे महत्वपूर्ण आवाज़ सत्ता के गलियारों से नहीं, बल्कि उन युवाओं से उठ रही है जो अपने भविष्य के साथ-साथ भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर भी सवाल उठा रहे हैं।

परीक्षा व्यवस्था के संकट से लोकतांत्रिक टकराव तक

भारत में शिक्षा और सार्वजनिक भर्ती परीक्षा प्रणाली को लेकर उपजा असंतोष अब एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका है। पिछले लगभग एक महीने से हजारों छात्र-छात्राएं और युवा शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में गहराते संकट के लिए जवाबदेही तय की जाए तथा परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बहाल की जाए। पिछले एक दशक में देशभर में केंद्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के 90 से अधिक पेपर लीक होने के मामले सामने आए हैं, जिनसे लगभग 7.5 करोड़ अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं।

राज कुमार सिन्हा

इनमें नीट-यूजी, यूजीसी-नेट, एसएससी तथा विभिन्न राज्यों की पुलिस और शिक्षक भर्ती परीक्षाएं शामिल हैं। भारत की 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 34.5 से 37.1 करोड़ युवा आबादी, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 27 प्रतिशत है, इस व्यवस्था से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई है। बार-बार परीक्षाओं के निरस्त होने, नियुक्तियों में देरी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की कार्यप्रणाली पर उठते सवालों ने लाखों युवाओं के भविष्य को अनिश्चितता में डाल दिया है।हर रद्द हुई परीक्षा और हर प्रश्नपत्र लीक के पीछे वर्षों की मेहनत, परिवारों का आर्थिक निवेश, मानसिक तनाव और टूटते सपने जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि यह आंदोलन केवल परीक्षा सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि युवाओं के रोजगार, महंगाई और भविष्य की सुरक्षा जैसे व्यापक प्रश्नों से भी जुड़ गया है।शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर तीन सप्ताह से आमरण अनशन कर रहे

पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाने के बाद आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जनसमर्थन मिला। इसके बाद छात्रों ने संसद तक मार्च का आह्वान किया।दिल्ली, मुंबई, पटना, बेंगलुरु सहित अनेक शहरों में कैंडल मार्च, धरने और प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। सिख समाज सहित अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा प्रदर्शनकारियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। बड़ी संख्या में आम नागरिक भी भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री भेजकर आंदोलन के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं। इस मानवीय सहयोग ने आंदोलन को सामाजिक संवेदना का भी स्वरूप प्रदान किया है।20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज तथा अन्य बल प्रयोग के माध्यम अपनाए। अनेक प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उनके विरुद्ध अत्यधिक बल प्रयोग किया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

आंदोलनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ सादे कपड़ों में मौजूद लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर हिंसा की तथा बैरिकेडिंग में करंट और कीलों वाली लाठियों का प्रयोग किया गया। पुलिस पर पैलेट गन के इस्तेमाल के भी आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग उठ रही है। सरकार ने जंतर-मंतर क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए, कई मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद किया तथा पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया। केंद्र सरकार ने जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शनों को संभालने के लिए 3000 अतिरिक्त सशस्त्र पुलिसकर्मी भेजे हैं। यह कदम दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर उठाया गया है।राजधानी के संवेदनशील हिस्सों जंतर-मंतर से संसद भवन तक खासतौर से इसके आसपास के इलाकों को पूरी तरह से छावनी में बदल दिया गया है. यहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। जमीनी घेराबंदी के अलावा दिल्ली की सुरक्षा को आधुनिक तकनीक से पूरी तरह से लैस किया गया है। इसके बावजूद अगले दिन भी बड़ी संख्या में छात्र आंदोलन स्थल पर पहुंचे और संघर्ष जारी रखने की घोषणा की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित अनेक विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में प्रदर्शन किया और गिरफ्तार हुए। उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, शरद पवार, सुप्रिया सुले, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह सहित कई नेताओं ने जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया। संसद में भी विपक्ष ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। एमनेस्टी इंटरनेशनल सहित कई मानवाधिकार संगठनों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग पर चिंता व्यक्त की और लोकतांत्रिक अधिकारों के सम्मान की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से अपनी बात रखने तथा धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि उनकी लड़ाई केवल किसी एक परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया की नहीं, बल्कि पूरी शिक्षा एवं भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही स्थापित करने की है। उनकी प्रमुख मांगों में परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक मामलों में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई, भर्ती प्रक्रियाओं की समयबद्धता, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में जवाबदेही तय करना तथा शिक्षा व्यवस्था में जनता का विश्वास बहाल करना शामिल है।यह आंदोलन अब केवल परीक्षा सुधार का प्रश्न नहीं रह गया है, बल्कि युवाओं के भविष्य, रोजगार और शासन की जवाबदेही से जुड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। यदि सरकार आंदोलनकारी छात्रों के साथ संवाद स्थापित कर उनकी मांगों पर ठोस और समयबद्ध निर्णय लेती है, तो स्थिति शांत हो सकती है और शिक्षा व्यवस्था में सुधार का रास्ता खुल सकता है। इसके विपरीत यदि केवल पुलिस बल और प्रशासनिक नियंत्रण के माध्यम से आंदोलन को दबाने का प्रयास जारी रहता है, तो युवाओं का असंतोष और व्यापक हो सकता है। ऐसी स्थिति में यह आंदोलन देशव्यापी छात्र-युवा अभियान का रूप लेकर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों को भी अपने साथ जोड़ सकता है। इससे संसद, न्यायपालिका और सरकार पर संस्थागत सुधारों का दबाव बढ़ने की संभावना है।

सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को मिली रफ्तार, 303 मास्टर ट्रेनर्स संभाल रहे पुलिस प्रशिक्षण की कमान

मीडिया ऑडीटर, भोपाल (निप्र)। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में शामिल सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को और अधिक गति देने के उद्देश्य से शुक्रवार को भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 'सिंहस्थ-2028: ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स कोर्स' का राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार में प्रदेशभर के प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि तथा सिंहस्थ-2028 की तैयारियों से जुड़े अधिकारियों ने भाग लिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिलों में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा, फील्ड अनुभवों का आदान-प्रदान, प्रशिक्षण मॉड्यूल में सुधार और आगामी रणनीति तय करना रहा। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) कैलाश मकवाणा ने कहा कि सिंहस्थ-

2028 केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम है ऐसे आयोजन की सफलता पुलिस बल की पेशेवर दक्षता, अनुशासन, संवेदनशीलता और विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय पर निर्भर करेगी उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस पिछले तीन वर्षों से योजनाबद्ध तरीके से सिंहस्थ की तैयारियों में जुटी हुई है। डीजीपी ने बताया कि फरवरी 2026 में उज्जैन में आयोजित मंथन और विशेषज्ञों के सेमिनार से मिले सुझावों के आधार पर व्यापक प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की गई इसके बाद अप्रैल 2026 की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में पुलिस ड्यूटी पोर्टल, आधारित मानव संसाधन प्रबंधन, साइबर सुरक्षा योजना तथा विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब राज्य स्तरीय सेमिनार के माध्यम से इन तैयारियों की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय की जा रही है।

303 मास्टर ट्रेनर्स पूरे प्रदेश में दे रहे प्रशिक्षण: डीजीपी कैलाश मकवाणा ने बताया कि पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए दो चरणों में कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इसके तहत प्रदेशभर में 303 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गए हैं जो अपने-अपने जिलों में हजारों पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भूमिका आधारित प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही प्रशिक्षित पुलिसकर्मी सिंहस्थ के दौरान मैदान में प्रत्यक्ष रूप से कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाएंगे। इसलिए प्रशिक्षण केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि पुलिस बल की कार्यकुशलता और सेवा भावना विकसित करने का माध्यम है।

आधुनिक तकनीक से मजबूत होगी व्यवस्थाएं: डीजीपी ने बताया कि सिंहस्थ-2028 के लिए आवश्यक पुलिस अधोसंरचना के विकास हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पहले ही शासन को भेजा जा चुका है, जिसे स्वीकृति मिल चुकी है और कई कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने बताया कि द्ध।ऋऋ प्रणाली अंतिम चरण में है, जिसके माध्यम से सिंहस्थ के दौरान हजारों पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी, तैनाती और मानव संसाधन प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाया जाएगा इसके साथ ही आधुनिक तकनीक आधारित पुलिसिंग और विभिन्न विभागों के बीच डिजिटल समन्वय पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। डीजीपी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ-2025 के दौरान मध्यप्रदेश पुलिस ने कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। अधिकारियों ने वहां जाकर भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण, आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन किया, जिनकी श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) को सिंहस्थ-2028 की तैयारियों में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के दौरान भीड़ प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रतिक्रिया, अंतरराज्यीय समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली सबसे महत्वपूर्ण विषय होंगे, जिन पर अभी से व्यापक तैयारी की जा रही है डीजीपी मकवाणा ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में वर्ष 2025 में 8,500 और वर्ष 2026 में 9,662 पुलिस पदों पर भर्ती की स्वीकृति मिली लगभग 18 हजार से अधिक नए पुलिसकर्मियों की भर्ती से पुलिस बल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी उन्होंने बताया कि लंबे समय बाद उप निरीक्षक और सूबेदार संवर्ग में भी भर्ती की गई है।

शिवपुरी जिला अस्पताल में गर्भवती के परिजनों और महिला गार्ड के बीच विवाद, सीसीटीवी फुटेज से होगी जांच

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शिवपुरी जिला अस्पताल के गायनिक वार्ड में शुक्रवार दोपहर एक गर्भवती महिला के परिजनों और महिला सुरक्षा गार्ड के बीच प्रवेश को लेकर विवाद हो गया परिजनों ने सुरक्षा गार्ड पर अभद्र व्यवहार, हाथ पकड़कर खींचने और थप्पड़ मारने की कोशिश करने का आरोप लगाया है घटना के बाद अस्पताल परिसर में कुछ देर तक तनाव की स्थिति बनी रही मामले की शिकायत मिलने पर अस्पताल प्रबंधन ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जानकारी के अनुसार नरवर निवासी सात माह की गर्भवती सीमा प्रजापति को अत्यधिक ब्लीडिंग होने पर जिला अस्पताल लाया गया। परिजनों का कहना है कि गुरुवार रात ही नरवर अस्पताल से भर्ती का पर्चा बन गया था लेकिन खराब मौसम और जंगल के रास्ते के कारण वे रात में शिवपुरी नहीं पहुंच सके शुक्रवार को अस्पताल पहुंचने पर पहले पुराने पर्चे पर भर्ती से इनकार किया गया बाद में औपचारिकताएं पूरी होने के बाद महिला को गायनिक वार्ड में भर्ती किया गया। मरीज की ननद चेतना प्रजापति ने आरोप लगाया कि भर्ती के बाद वह कार की चाबी देने के लिए वार्ड से बाहर आई थीं इसी दौरान गेट पर तैनात महिला सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोकते हुए हाथ पकड़कर खींचा और थप्पड़ मारने की कोशिश की विरोध करने पर पुलिस बुलाने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया परिजनों का कहना है कि बाहर मौजूद अन्य सदस्य के साथ भी गार्ड ने अभद्र व्यवहार किया। वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज के साथ पहले से दो अटेंडरों को वार्ड में प्रवेश की अनुमति दी गई थी। जब अतिरिक्त परिजन अंदर जाने का प्रयास करने लगे तो सुरक्षा नियमों के तहत उन्हें रोका गया, जिसके बाद विवाद की स्थिति बनी।

एमसीबी में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर सख्ती, अपर कलेक्टर ने दिए समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, अभिलेखों की शुद्धता और डिजिटल सेवाओं को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को ग्राम पंचायत लाई स्थित अमृतधारा डीपीआरसी भवन में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक की अध्यक्षता अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार एवं नम्रता डोंगरे ने की बैठक कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार आयोजित हुई, जिसमें सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे बैठक में अपर कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि नामांतरण, खाता विभाजन, सीमांकन, त्रुटि सुधार, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई अनुमति सहित सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए उन्होंने कहा कि राजस्व अभिलेखों की शुद्धता, पारदर्शिता और समयबद्ध सेवा वितरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने अधिकारियों को ई-कोर्ट प्रणाली का प्रभावी उपयोग करते हुए लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए। साथ ही नक्शा बंटांकन, मैनुअल नक्शा संशोधन, मॉडर्न रिकॉर्ड रूम, अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा स्वामित्व योजना के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर जोर दिया बैठक में 'एग्रीस्टैक' योजना के तहत किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन एवं डेटा सत्यापन सुनिश्चित करने, डिजिटल किसान किताब की प्रगति बढ़ाने तथा पात्र किसानों को डिजिटल सेवाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए अपर कलेक्टर ने ऑटो डायवर्सन, लैंड बैंक, उच्च न्यायालय से संबंधित लंबित प्रकरणों को समय पर पूर्ण करने पर विशेष बल दिया। पर कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों, भू-अर्जन, लोक आयोग, पीजी पोर्टल, मुख्यमंत्री जनदर्शन, जन शिकायत और ई-समाधान पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों और राजस्व प्रकरणों के निपटारे में अनावश्यक विलंब या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी बैठक के अंत में उन्होंने सभी अधिकारियों से पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक राजस्व कार्य का प्रभावी क्रियान्वयन करने का आह्वान किया।

ग्राम डोड़की में हैंडपंपों का क्लोरीनेशन अभियान सफल, स्वच्छ पेयजल से जलजनित बीमारियों की रोकथाम पर जोर

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। वर्षा ऋतु के दौरान जलजनित बीमारियों की रोकथाम और ग्रामीणों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनेन्द्रगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत डोड़की में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग द्वारा विशेष क्लोरीनेशन अभियान चलाया गया अभियान के तहत गांव के सभी सार्वजनिक हैंडपंपों का वैज्ञानिक तरीके से क्लोरीनेशन कर पेयजल को संक्रमण मुक्त और सुरक्षित बनाया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता आकाश पोद्दार के निर्देश पर विभाग की तकनीकी टीम एवं हैंडपंप टेक्निशियनों ने निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रत्येक सार्वजनिक हैंडपंप में 30 एमएल क्लोरीन का उपयोग कर क्लोरीनेशन की प्रक्रिया पूरी की इस प्रक्रिया से पानी में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं, बैक्टीरिया एवं अन्य संक्रमण फैलाने वाले सूक्ष्मजीवों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया गया जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यवर्धक पेयजल उपलब्ध हो सके। अभियान के दौरान विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल के महत्व के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी उन्होंने बताया कि वर्षा ऋतु में दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड, हैजा जैसी जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में जल स्रोतों का नियमित क्लोरीनेशन, साफ-सफाई और पानी की गुणवत्ता की निगरानी बेहद आवश्यक है। ग्रामीणों को हैंडपंपों और अन्य जल स्रोतों के आसपास स्वच्छता बनाए रखने, गंदगी नहीं फैलाने तथा जल संरक्षण को जनभागीदारी का अभियान बनाने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही यह भी समझाया गया कि यदि जल स्रोत स्वच्छ रहेंगे तो पेयजल की गुणवत्ता लंबे समय तक सुरक्षित बनी रहेगी और बीमारियों का खतरा स्वतः कम होगा ग्राम डोड़की के ग्रामीणों ने विभाग की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि नियमित क्लोरीनेशन से पेयजल की गुणवत्ता में सुधार होगा और जलजनित रोगों से बचाव में मदद मिलेगी ग्रामीणों ने जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने तथा सुरक्षित पेयजल के संरक्षण में सक्रिय सहयोग देने का संकल्प भी व्यक्त किया लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में क्लोरीनेशन, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं विभाग का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल पहुंचाना तथा जलजनित रोगों की प्रभावी रोकथाम सुनिश्चित कर स्वस्थ एवं स्वच्छ ग्रामीण समाज का निर्माण करना है।

चनवारीडांड प्लास्टिक प्रतिबंध इकाई का संभागीय उपायुक्त ने किया निरीक्षण, वैज्ञानिक प्लास्टिक प्रबंधन की सराहना

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से संचालित प्रयासों के तहत सरगुजा संभाग के उपायुक्त आर.के. खूंटे ने शुक्रवार को चनवारीडांड स्थित प्लास्टिक प्रतिबंध इकाई का निरीक्षण किया उन्होंने इकाई में प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण, छंटाई, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निपटान की व्यवस्था का गहन अवलोकन करते हुए कार्यप्रणाली की सराहना की साथ ही अधिकारियों को प्लास्टिक प्रबंधन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने इकाई में रखे अभिलेखों और संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे का व्यवस्थित संग्रहण, पृथक्करण और सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने से प्रदूषण कम होगा तथा स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण का निर्माण होगा। उन्होंने जनपद पंचायत क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, सूखे एवं गीले कचरे का पृथक्करण तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया उपायुक्त ने निर्देश दिए कि प्रत्येक पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को मजबूत किया जाए और प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान के लिए आवश्यक संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए आर.के. खूंटे ने अधिकारियों एवं मैदानी अमले से कहा कि ग्रामीणों के बीच एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए साथ ही लोगों को घर स्तर पर कचरे का पृथक्करण, प्लास्टिक अपशिष्ट के सुरक्षित संग्रहण तथा पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के लिए प्रेरित किया जाए।

नैनो डीएपी से आधुनिक खेती की ओर बढ़े किसान अनिल मिश्रा, बेहतर उत्पादन और कम लागत की उम्मीद

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। आधुनिक और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नैनो उर्वरकों के उपयोग के प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है इसका सकारात्मक असर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगा है। एमसीबी जिले के विकासखंड मनेन्द्रगढ़ के ग्राम पसौरी निवासी किसान अनिल मिश्रा ने इस खरीफ सीजन में पहली बार अपनी फसल में नैनो डीएपी का उपयोग करने का निर्णय लिया है उन्हें उम्मीद है कि इस नई तकनीक से फसल की बढ़वार बेहतर होगी उत्पादन

में वृद्धि होगी और खेती की लागत भी कम आएगी। अनिल मिश्रा ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति से नैनो डीएपी प्राप्त कर अपनी खेती में इसका प्रयोग शुरू किया है उनका कहना है कि बदलते समय के साथ किसानों को भी आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना चाहिए ताकि कम लागत में अधिक उत्पादन हासिल किया जा सके उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उनके गांव और आसपास के कई किसानों ने नैनो डीएपी का उपयोग किया था, जिसके परिणाम काफी उत्साहजनक रहे उन किसानों की फसलों की बेहतर बढ़वार और उत्पादन देखकर उन्हें भी इस तकनीक पर विश्वास हुआ और इस बार उन्होंने स्वयं इसका उपयोग करने का निर्णय लिया। अनिल मिश्रा ने बताया कि नैनो डीएपी पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में उपयोग में अधिक सुविधाजनक है पहले जहां किसानों को उर्वरक की भारी बोरियां ढोनी पड़ती थीं वहीं अब नैनो डीएपी की छोटी बोतल को आसानी से बैग में रखकर ले जाया जा सकता है इससे परिवहन में सुविधा होती है समय और श्रम दोनों की बचत होती है तथा उर्वरक का उपयोग भी अधिक वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि नैनो डीएपी के प्रयोग से उनकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होगा साथ ही खेती की लागत कम होने से आर्थिक लाभ भी बढ़ेगा।

साइबर जागरूकता से सशक्त होंगी बेटियां: बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ऑनलाइन सुरक्षा प्रशिक्षण का दूसरा दिन संपन्न

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से बालिकाओं को सुरक्षित रखने और उन्हें तकनीक का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने के लिए जागरूक बनाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के तहत ऑनलाइन सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता कार्यक्रम का द्वितीय दिवस शुक्रवार को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठारी में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा, मानव तस्करी, विधिक अधिकार, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय सुरक्षा तथा विभिन्न हेल्पलाइन सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई कार्यक्रम का आयोजन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संतन देवी जांगड़े के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक रत्ना सिंह के सहयोग से किया गया कार्यक्रम का संचालन जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र (हब), महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला मिशन समन्वयक तारा कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इंटरनेट और सोशल मीडिया आज शिक्षा, संचार और जानकारी का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुके हैं लेकिन इनके बढ़ते उपयोग के साथ साइबर अपराधों की घटनाओं में भी लगातार वृद्धि हो रही है ऐसे में विशेष रूप से किशोरियों और महिलाओं के लिए ऑनलाइन सुरक्षा संबंधी जानकारी होना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है उन्होंने कहा कि जागरूकता ही साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी हथियार है और सही जानकारी के माध्यम से ही डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाया जा सकता है। पुलिस विभाग के अधिकारियों ने छात्राओं को साइबर अपराधों के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया फ्रॉड, फर्जी लिंक, ऑनलाइन ठगी, साइबर बुलिंग, फर्जी आईडी, ओटीपी धोखाधड़ी, डिजिटल ब्लैकमेल और ऑनलाइन शोषण जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं विशेषज्ञों ने समझाया कि किसी भी अनजान व्यक्ति से मित्रता करने, संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने, बैंकिंग संबंधी जानकारी साझा करने अथवा ओटीपी बताने जैसी छोटी-सी लापरवाही भी गंभीर आर्थिक और सामाजिक नुकसान का कारण बन सकती है उन्होंने छात्राओं से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत पुलिस और साइबर हेल्पलाइन से संपर्क करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रतिनिधि अंजनी यादव ने छात्राओं को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कानूनों की जानकारी दी उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम, महिला संरक्षण कानून, साइबर अपराध से संबंधित कानूनी प्रावधान तथा निःशुल्क कानूनी सहायता की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया उन्होंने कहा कि प्रत्येक बालिका को अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक है क्योंकि जागरूक नागरिक ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रेरित कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान अजय विश्वकर्मा ने मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध पर विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि रोजगार, शिक्षा, मॉडलिंग, विवाह या अन्य आकर्षक प्रस्तावों के नाम पर कई बार अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं।

शिवपुरी में बीआरसीसी पद पर बदलाव, अतरसिंह राजौरिया को मिला अतिरिक्त प्रभार

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शिवपुरी जनपद शिक्षा केंद्र में ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर (बीआरसीसी) पद पर प्रशासनिक बदलाव किया गया है लंबे समय से इस पद पर कार्यरत बालकृष्ण ओझा के इस्तीफे के बाद कलेक्टर अर्पित वर्मा ने जिला शिक्षा केंद्र में पदस्थ एपीसी अतरसिंह राजौरिया को आगामी आदेश तक बीआरसीसी का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है राजौरिया ने शुक्रवार दोपहर जनपद शिक्षा केंद्र पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया जानकारी के अनुसार बालकृष्ण ओझा ने पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से वे पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते बीआरसीसी के दायित्वों के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे इस दौरान वे कई बार लंबी छुट्टी पर भी रहे जिससे जनपद शिक्षा केंद्र से जुड़े शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की गति प्रभावित हुई। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने तत्काल व्यवस्था के तहत एपीसी अतरसिंह राजौरिया को अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। वे अपने मूल दायित्वों के साथ बीआरसीसी की जिम्मेदारी भी निभाएंगे उनके कार्यभार संभालने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और विभिन्न शिक्षक संगठनों ने उनका स्वागत करते हुए सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) दफेदार सिंह सिकरवार ने बताया कि बालकृष्ण ओझा ने पारिवारिक दायित्वों के कारण पद छोड़ने का निर्णय लिया था उन्होंने पुष्टि की कि आगामी आदेश तक अतरसिंह राजौरिया को शिवपुरी बीआरसीसी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

मंदसौर में 24 घंटे में हुई 1 इंच बारिश, अगले 4 दिन बारिश के आसार, अब 1 दिन छोड़ कर होगी पानी की सप्लाई

मीडिया ऑडीटर,मंदसौर (निप्र)। मंदसौर जिले में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में जिले में करीब एक इंच बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही जिले में इस सीजन की कुल वर्षा 13.28 इंच तक पहुंच गई है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं खेतों में नमी बढ़ने से सोयाबीन, मक्का, उड़द सहित खरीफ फसलों को भी फायदा मिल रहा है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक जिले में रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है।

जिलेभर में रुक-रुककर होती रही बारिश: गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक जिले में रुक-रुककर बारिश का दौर चलता रहा। शुक्रवार को भी पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे और कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी होती रही। जिला मुख्यालय के अलावा सीतामऊ, नाहरगढ़, भावगढ़, गरोठ, सुवासरा, शामगढ़, दलौदा, मल्हारगढ़, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़, डिगांव, बरखेड़ा और अफजलपुर सहित

जिले के अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई।

जल स्त्रोतों में बढ़ा पानी, बदलेगी पेयजल व्यवस्था: बारिश की कमी के कारण पिछले कुछ समय से जिले के जल स्त्रोतों का जलस्तर घट गया था। इसके चलते नगर पालिका शहर में दो दिन छोड़कर पेयजल आपूर्ति कर रही थी। अब लगातार हो रही बारिश के बाद जल स्त्रोतों में पानी बढ़ा है। इसे देखते हुए नगर पालिका ने शनिवार से एक दिन छोड़कर पेयजल सप्लाई करने का निर्णय लिया है।

● खरीफ फसलों के लिए फायदेमंद बारिश

किसानों का कहना है कि समय पर हुई यह बारिश खरीफ फसलों के लिए काफी लाभदायक साबित होगी। सोयाबीन, मक्का, उड़द और अन्य फसलों की बढ़वार के लिए खेतों में पर्याप्त नमी मिल गई है।

● अगले चार दिन बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार जिले में अगले चार दिनों तक रुक-रुककर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। इस दौरान अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।

● चार दिन का मौसम पूर्वानुमान

25 जुलाईः बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
26 जुलाईः जिले के अधिकांश हिस्सों में मध्यम बारिश होने की संभावना है।
27 जुलाईः रुक-रुककर बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं।

● मौसम विभाग ने जारी की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को गरज-चमक के दौरान विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर नहीं रुकें और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर ही रहें।

सागर में युवती पर कुल्हाड़ी से हमला करने वाले गिरफ्तार, आपसी विवाद में पड़ोसियों ने किया था वार, तीन आरोपी गिरफ्तार

मीडिया ऑडीटर, सागर सागर के मोतीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सोमला में युवती पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से थाने में पूछताछ के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, 22 जुलाई को बीएमसी अस्पताल में भर्ती ग्राम सोमला निवासी 22 वर्षीय सोना कुर्मी के बयान दर्ज किए गए। पीड़िता ने बताया कि सुमन कुर्मी, सत्तू उर्फ सत्यनारायण कुर्मी और रामकुमार कुर्मी, तीनों निवासी ग्राम सोमला, ने उसके साथ गाली-गलौज की और उसे पकड़ लिया। पीड़िता के अनुसार, इसी दौरान सुमन कुर्मी ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों के सामने आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।

हत्या की कोशिश का मामला दर्ज: शिकायत के आधार पर मोतीनगर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीम बनाई गई।पुलिस ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए सुमन कुर्मी, सत्तू उर्फ सत्यनारायण कुर्मी और रामकुमार कुर्मी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना करना स्वीकार किया। मोतीनगर थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया।

गढ़ाकोटा पुलिस ने अवैध शराब के साथ पकड़े चार आरोपी, ब्रांडेड शराब-बीयर की बड़ी खेप जब्त, शराब तस्करी का नेटवर्क खंगाल रही पुलिस

मीडिया ऑडीटर,सागर (निप्र)। सागर जिले की गढ़ाकोटा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर ब्रांडेड अंग्रेजी शराब और बीयर की बड़ी खेप बरामद की है। कार्रवाई के दौरान चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि उनके पास शराब कहां से आई और इसकी सप्लाई किसके लिए की जा रही थी।

मुखबिर की सूचना पर दी दबिश: पुलिस के अनुसार, मुखबिर से सूचना मिलने के बाद अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान ग्राम चनौआ निवासी सुंदर पिता भुजवल कुर्मी के कब्जे से विभिन्न ब्रांडों की 112 पाव यानी करीब 20.16 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 14 हजार 700 रुपए बताई गई है।

अलग-अलग आरोपियों से शराब और बीयर बरामद: पुलिस ने ग्राम चनौआ खुर्द निवासी सहदेव पिता रतिराम नामदेव के कब्जे से विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब और बीयर जब्त की। इसी तरह मोतीनगर के शास्त्री वार्ड निवासी कमलेश पिता धनप्रसाद पटेल के पास से भी शराब और बीयर बरामद की गई।

गढ़ाकोटा से भी शराब की खेप जब्त: एक अन्य कार्रवाई में किला वार्ड गढ़ाकोटा निवासी मुलू उर्फ धरमदास पिता बालकिशन पटेल के कब्जे से विभिन्न ब्रांडों की 21.18 लीटर अवैध शराब और बीयर बरामद की गई। पुलिस के अनुसार, जब्त शराब की अनुमानित कीमत 9 हजार 520 रुपए है।

सीहोर में अब तक 17.65 इंच बारिश, पिछले साल से 1.58 इंच कम,आष्टा में सबसे ज्यादा और श्यामपुर में सबसे कम बारिश दर्ज

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले में मानसून सीजन के दौरान 1 जून से 24 जुलाई तक औसतन 17.65 इंच (448.31 मिमी) बारिश दर्ज की गई है। भू-अभिलेख विभाग के अनुसार यह पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 19.23 इंच (488.44 मिमी) वर्षा की तुलना में 1.58 इंच कम है। जिले की सामान्य औसत वर्षा 45.21 इंच (1148.33 मिमी) मानी जाती है, जिसके मुकाबले अब तक करीब 39 प्रतिशत बारिश ही दर्ज हुई है।

आष्टा में सबसे ज्यादा, श्यामपुर में सबसे कम बारिश: जिले के वर्षामापी केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार इस सीजन में आष्टा में सर्वाधिक 20.87 इंच (530.19 मिमी) वर्षा रिकॉर्ड की गई है। वहीं श्यामपुर में सबसे कम 12.18 इंच (309.37 मिमी) बारिश दर्ज हुई।

अन्य प्रमुख केंद्रों की स्थिति इस प्रकार रही: रेहटीः 19.54 इंच (496.31 मिमी), जावरः 18.86 इंच (479.04 मिमी)

भैरूंदाः 18.46 इंच (468.88 मिमी), बुधनीः 17.99 इंच (456.94 मिमी), इच्छावरः 17.72 इंच (450.08 मिमी), सीहोर मुख्यालयः 15.63 इंच (397.00 मिमी), 24 जुलाई को केवल दो केंद्रों पर हुई बारिश।

24 जुलाई को जिले के केवल दो वर्षामापी केंद्रों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। श्यामपुर में 0.10 इंच (2.54 मिमी) और आष्टा में 0.04 इंच (1.01 मिमी) वर्षा हुई। जबकि सीहोर, जावर, इच्छावर, भैरूंदा, बुधनी और रेहटी में बारिश दर्ज नहीं की गई। जिले की औसत दैनिक वर्षा 0.016 इंच (0.40 मिमी) रही।

अगले 72 घंटे में तेज बारिश की संभावना: मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मध्य प्रदेश के मध्य हिस्से में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो रहा है।

झाड़ी में छिपे बैठे भालू ने किया छात्र पर हमला

पेट और पैर नोचे, 30 टांके आए, कुत्ते ने भौंक कर बचाई जान, हालत खतरे से बाहर

मीडिया इटारसी (निप्र)। नर्मदापुरम जिले के इटारसी से भालू के हमले का मामला सामने आया है। यहां के केसला ब्लॉक के सुखतवा क्षेत्र के जंगल में अपनी गाय लाने गए 16 वर्षीय छात्र पर झाड़ियों में छिपे भालू ने हमला कर दिया। भालू के पंजों से छात्र के पेट और पैर में गहरे घाव हैं। उसे 30 टांके आए हैं। घटना गुरुवार शाम करीब 5 बजे की है।

4-5 मिनट तक भालू के चंगुल में फंसा रहा: घायल विकलेश कासदे 11वीं कक्षा का छात्र है। उसने बताया कि वह अपनी गाय लेने छींदापानी भीलट देव जंगल गया था, तभी अचानक 4 से 5 फीट ऊंचा भालू झाड़ियों से निकलकर उस पर टूट पड़ा। भालू ने उसे जमीन पर गिरा दिया और करीब 4-5 मिनट तक पंजों से हमला करता रहा। भालू ने

अपने पंजों से पेट और पैर को बुरी तरह नोच डाला।

पालतू कुत्ते ने दिखाई बहादुरी: विकलेश के साथ उसका पालतू कुत्ता भी जंगल गया था। उसने लगातार भौंकते हुए भालू पर हमला कर दिया। कुत्ते के आक्रामक होने पर भालू घबरा गया और जंगल की ओर भाग निकला। इसके बाद घायल छात्र ने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। घर जंगल से करीब दो किलोमीटर दूर होने के कारण परिजन और ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे अस्पताल पहुंचाया।

मजदूर परिवार ने मांगी वन विभाग से मदद: विकलेश के पिता रमेश कासदे ने बताया कि वे मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। उनके पांच बच्चे हैं और विकलेश चौथे नंबर का बेटा है। उन्होंने वन विभाग से आर्थिक सहायता और क्षेत्र में वन्यजीवों से सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

डॉक्टर बोले- पेट और पैर पर गहरे घाव: परिजन रात करीब 10 बजे घायल को इटारसी के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे। ड्यूटी डॉक्टर डॉ. अनिकेत सिंह ने बताया कि भालू के पंजों और दांतों से पेट व पैर पर गहरे घाव हुए थे।

खून का बहाव रोकने और घावों के उपचार के लिए 30 टांके लगाए गए हैं। फिलहाल छात्र की हालत स्थिर है और उसका इलाज जारी है।

पन्ना में युवक पर कुल्हाड़ी-लाठियों से हमलाः पुरानी रंजिश में घात लगाकर बैठे थे आरोपी, सिर में 15 टांके आए

मीडिया ऑडीटर, पन्ना (निप्र)। पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम नमी झालर (जनवार) में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। बाबूलाल यादव (30 वर्ष) पर कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला तब हुआ जब वह अपनी किराना दुकान जा रहे थे। इस हमले में बाबूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें जिला अस्पताल पन्ना में भर्ती कराया गया है। परिजनों के अनुसार, ग्राम नमी झालर निवासी बाबूलाल यादव जब दुकान जा रहे थे, तभी रास्ते के दोनों ओर झाड़ियों में घात लगाकर बैठे आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला। हमलावरों ने बाबूलाल के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे उन्हें गहरा घाव हुआ और 15 टांके आए। लाठियों के वार से उनकी पीठ और हाथों में भी गंभीर चोटें आई हैं। हमले के बाद वह खून से लथपथ होकर मौके पर ही बेहोश हो गए थे।

शोर मचाने पर भागे आरोपी: घटना के समय बाबूलाल की मां भी वहीं से गुजर रही थीं। बेटे को खून से लथपथ देखकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और ग्रामीणों को मदद के लिए बुलाया।

इटारसी स्टेशन पर 44 लाख के गहने पकड़े, 2 सराफा व्यावारियों के पास 19 किलो आभूषण के दस्तावेज नहीं मिले

मीडिया ऑडीटर, इटारसी (निप्र)। जीआरपी इटारसी ने बुधवार शाम चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन से करीब 19 किलोग्राम चांदी के आभूषण जब्त किए। गहनों का वजन 18.994 किलोग्राम है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 44 लाख रुपए बताई गई है। मौके पर आभूषणों से संबंधित वैध बिल, टैक्स दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत न किए जाने पर जीआरपी ने कार्रवाई करते हुए मामले की सूचना जीएसटी विभाग को भेज दी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 के जबलपुर छोर पर पुलिस और आरपीएफ ने दो सराफा व्यापारियों की जांच की। पूछताछ में उनकी पहचान भोपाल निवासी राकेश जाट (41) और लक्की राजवानी (44) के रूप में हुई।

स्कूली बच्चों को दिया गया आपदा प्रबंधन का व्यवहारिक प्रशिक्षण

एसडीआरएफ टीम ने बाढ़, अग्निकांड, सर्पदंश और आकाशीय बिजली से बचाव के बताए उपाय

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशानुसार जिले के शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आपदा प्रबंधन संबंधी व्यावहारिक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने तथा आपदा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से गुरुवार को विदिशा तहसील के ग्राम अहमदपुर स्थित अग्रवाल स्कूल में आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला सेनानी श्री मयंक कुमार जैन के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विद्यार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं के दौरान सुरक्षित रहने के उपायों की विस्तार से जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने बाढ़ की स्थिति में बचाव के तरीके, सर्पदंश होने पर बरती जाने वाली सावधानियां, अग्नि दुर्घटनाओं के समय

सुरक्षित निकासी की प्रक्रिया, आकाशीय बिजली गिरने की स्थिति में अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय तथा प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) की महत्वपूर्ण जानकारी सरल एवं व्यवहारिक तरीके से समझाई। प्रशिक्षकों ने विद्यार्थियों को बताया कि आपदा के समय घबराने के बजाय सूझबूझ और सही जानकारी के साथ कार्य करने से जनहानि एवं संपत्ति के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। साथ ही बच्चों से अपील की गई कि वे प्रशिक्षण में सीखी गई बातों को अपने परिवार एवं आसपास के लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे समाज में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ सके। प्रशिक्षण का संचालन विदिशा एसडीआरएफ टीम के प्रभारी कंपनी कमांडर श्री देवी सिंह परते के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान टीम के सदस्य देवेंद्र कटोरिया, संजय, गौरव रघुवंशी एवं संदीप ने विभिन्न आपदा परिस्थितियों से निपटने का प्रायोगिक प्रदर्शन किया। उन्होंने बचाव एवं राहत कार्यों का जीवंत प्रदर्शन कर विद्यार्थियों को आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाई जाने वाली तकनीकों से अवगत कराया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने आपदा प्रबंधन से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे, जिनका एसडीआरएफ टीम द्वारा विस्तारपूर्वक समाधान किया गया। प्रशिक्षण में विद्यालय के शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए आपदा प्रबंधन के महत्व को समझा और भविष्य में ऐसी परिस्थितियों में सतर्क एवं जागरूक रहने का संकल्प लिया।

मुंबई रूट पर भारी बारिश का असर, अवंतिका एक्सप्रेस समेत 8 ट्रेनें रहेगी रद्द, कई स्टेशनों पर फंसे यात्रियों को भोजन-पानी उपलब्ध कराया गया

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। मुंबई रेल मंडल के घोलवड-उमरगाम रोड रेलखंड में भारी बारिश के कारण हुए जलभराव का असर दूसरे दिन भी रेल यातायात पर बना हुआ है। रेल परिचालन प्रभावित होने के चलते रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का संचालन शुक्रवार को भी प्रभावित रहेगा। रेलवे ने 8 ट्रेनों को उनके प्रारंभिक स्टेशनों से रद्द कर दिया है, जबकि 6 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और शॉर्ट ओरिजिनेट किया गया है।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार को घोलवड-उमरगाम रेलखंड के बीच स्थित ब्रिज क्रमांक-203 पर जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। सुरक्षा कारणों से इस सेक्शन पर रेल परिचालन अस्थायी रूप से प्रभावित करना पड़ा, जिससे दिल्ली-मुंबई रेल मार्ग की कई ट्रेनें प्रभावित हुई। मुंबई की ओर जाने वाली अनेक ट्रेनों को रतलाम मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर रोका गया।

यात्रियों के लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था: रतलाम, नामली,

नागदा, मेघनगर, लिमखेड़ा, थांदला रोड और बामनिया स्टेशनों पर रुकी ट्रेनों के यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने दाल-चावल, खिचड़ी, पोहा, केले और पेयजल की व्यवस्था की। इस सेवा कार्य में रतलाम के बोहरा समाज सहित कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने भी सहयोग किया।

ट्रेनों के देरी से रतलाम स्टेशन पर आने पर यात्रियों के लिए बोहरा समाज समेत रेलवे ने खान-पान की व्यवस्था की। ट्रेनों के देरी से रतलाम स्टेशन पर आने पर यात्रियों के लिए बोहरा समाज समेत रेलवे ने खान-पान की व्यवस्था की।

आरंभिक स्टेशनों से इन ट्रेनों को किया रद्दः 24 जुलाई को इंदौर से चलने वाली ट्रेन संख्या 12228 इंदौर-मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस। 24 जुलाई को बांद्रा टर्मिनस से चलने वाली ट्रेन संख्या 19019 बांद्रा टर्मिनस-हरिद्वार एक्सप्रेस। 24 जुलाई को ट्रेन संख्या 12962 इंदौर-मुम्बई सेंट्रल अवंतिका एक्सप्रेस। 24 जुलाई को गाड़ी संख्या 12995 बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस-अजमेर। 25 जुलाई को देहरादून से चलने वाली ट्रेन संख्या 19020 हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस। 25 जुलाई ट्रेन संख्या 12904 अमृतसर-मुंबई सेंट्रल गोल्डन टेम्पल मेल। 25 जुलाई को ट्रेन संख्या 12926 अमृतसर मुंबई सेंट्रल पश्चिम एक्सप्रेस। 26 जुलाई को बरौनी से चलने वाली ट्रेन संख्या 19038 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस।

इन ट्रेनों को किया शॉर्ट टर्मिनेट/ शॉर्ट ओरिजिनेट: जयपुर से चली गाड़ी संख्या 12980 जयपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस वडोदरा रेलवे स्टेशन से शॉर्टटर्मिनेट की गई। वडोदरा-बांद्रा टर्मिनस स्टेशन के मध्य निरस्त रहेगी। बांद्रा टर्मिनस से चलने वाली ट्रेन संख्या 12979 बांद्रा टर्मिनस -जयपुर एक्सप्रेस वडोदरा रेलवे स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। बांद्रा टर्मिनस-वडोदरा स्टेशन के बीच रद्द रहेगी। एर्नाकुलम से चलने वाली वाली ट्रेन संख्या 22655 एर्नाकुलम निजामुद्दीन एक?सप्रेस, एर्नाकुलम उमरगाम रोड रेलवे स्टेशन से शॉर्टटर्मिनेट होगी। उमरगाम रोड-निजामुद्दीन स्टेशन के मध्य निरस्त रहेगी। दाहोद से चलने वाली ट्रेन संख्या 19012 दाहोद-वलसाड इंटरसिटी एक्सप्रेस कोसाड रेलवे स्टेशन से शॉर्ट ओरिजिनेट होगी। कोसाड-वलसाड स्टेशन के बीच निरस्त रहेगी। हिसार से चलने वाली ट्रेन संख्या 04727 हिसार-वलसाड साप्ताहिक स्पेशल मारोली रेलवे स्टेशन से शॉर्ट टर्मिनेट होगी। मारोली-वलसाड स्टेशन के मध्य निरस्त रहेगी।

अमृतसर से चलने वाली ट्रेन संख्या 12904 अमृतसर-मुंबई सेंट्रल गोल्डन टेम्पल मेल रतलाम रेलवे स्टेशन से शॉर्टटर्मिनेट होगी। रतलाम-मुंबई सेंट्रल स्टेशन के मध्य निरस्त रहेगी।

रेलवे ने यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति की जानकारी लेने की अपील की है।

'मां के लिए था वो सेलिब्रेशन'

परिवार और कोच को समर्पित किया वैभव ने इंटरनेशनल करियर का पहला अर्धशतक

हरारे ,एजेसीं। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक लगाया। वैभव ने कहा कि करियर की शुरुआत में ही अच्छा प्रदर्शन करना आने वाले मैचों के लिए आत्मविश्वद्वड्डास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। 15 वर्षीय वैभव टी20 इंटरनेशनल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने 19 गेंदों में 50 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए। वैभव ने 15 साल 118 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया। उन्होंने लुई ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने इस फॉर्मेट में 16 साल और 56 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था। वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले भी सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में नेपाल के कुशल मल्ला को पीछे छोड़ा है। कुशल ने साल 2020 में अमेरिका के खिलाफ 15 साल और 340 दिन की उम्र में अर्धशतक लगाया था। बीसीसीआई डॉट टीवी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में उन्होंने कहा, 'जब आप अपने करियर के शुरुआती दौर में होते हैं और आपको ऐसी पारियां खेलने को मिलती हैं और आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो इससे आने वाले मैचों के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी लय में था और मैंने बस अपनी ताकत का इस्तेमाल किया; बस इतना ही। मैं यह अर्धशतक अपने परिवार, अपने कोच और उन सभी लोगों को समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने मेरे अच्छे और बुरे दौर में मेरा साथ दिया है। '

अर्धशतक पूरा करने के बाद, उन्होंने अपने सिर के ऊपर दोनों हाथों से 'ए' का निशान बनाया। अपने सेलिब्रेशन के बारे में बताते हुए इस युवा खिलाड़ी ने साफ किया कि यह सेलिब्रेशन असल में उनकी मां आरती के लिए एक सम्मान था। उन्होंने 'थंब्स अप' का इशारा भी किया, जिसके बारे में उन्होंने बताया, 'मैंने वह सेलिब्रेशन अपनी मां के लिए किया था, और दूसरा इशारा रिंकू सिंह के साथ हुई बातचीत पर आधारित था। '

जोस बटलर के नाम जुड़ी बड़ी उपलब्धि

नई दिल्ली ,एजेसीं। इंग्लैंड के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर टी20 क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। बटलर ने इस मामले में वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया है। बटलर ने यह मुकाम द हंड्रेड टूर्नामेंट में हासिल किया। उन्होंने मैनचेस्टर सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हुए लंदन स्पिरिट के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 11 गेंदों में 16 रनों की पारी खेलने के साथ ही यह मुकाम हासिल किया। बटलर के नाम अब टी20 क्रिकेट में 14,572 रन

क्रिस गेल का तोड़ा रिकॉर्ड

दर्ज हो गए हैं। बटलर क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 9 शतक और 102 अर्धशतक लगा चुके हैं। उन्होंने 16 रन बनाने के साथ ही क्रिस गेल को पीछे छोड़ा। गेल ने टी20 क्रिकेट में खेली 455 पारियों में 14,562 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक और 88 अर्धशतक निकले हैं। टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कीरोन पोलार्ड के नाम है, जिन्होंने 663 पारियों में 14,803 रन बनाए हैं। पोलार्ड ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 2 शतक और 70 अर्धशतक लगाए हैं। पोलार्ड से आगे निकलने के लिए बटलर को अब सिर्फ 231 रनों की दरकार है। टी20 विश्व कप 2026 में रनों के लिए संघर्ष करने वाले बटलर अपनी शानदार फॉर्म में लौट चुके हैं। हाल ही में भारत के खिलाफ खेली गई टी20 इंटरनेशनल सीरीज में बटलर का प्रदर्शन लाजवाब रहा था। उन्होंने पांचवें टी20 मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए महज 64 गेंदों में 131 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी। 5 मैचों की सीरीज में बटलर ने 43 की औसत और 182 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 175 रन बनाए थे। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में बटलर फिलहाल तीसरे नंबर पर काबिज हैं। बटलर ने इस फॉर्मेट में खेले 160 मुकाबलों में 148 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 4,212 रन बनाए हैं। इस दौरान वह 28 अर्धशतक और 2 शतक लगा चुके हैं। बटलर से आगे इस लिस्ट में सिर्फ रोहित शर्मा और बाबर आजम हैं। रोहित टी20 इंटरनेशनल से पहले ही संन्यास ले चुके हैं और उनके नाम 4,231 रन दर्ज हैं। वहीं, बाबर 4,596 रनों के साथ पहले स्थान पर मौजूद हैं।

टी20 में गेल से ज्यादा हुए बटलर के रन

जोस बटलर के नाम अब टी20 क्रिकेट में 14,572 रन दर्ज हो गए हैं। वह क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 9 शतक और 102 अर्धशतक लगा चुके हैं। गेल ने टी20 क्रिकेट में खेली 455 पारियों में 14,562 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक और 88 अर्धशतक निकले हैं। टी20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कीरोन पोलार्ड के नाम है, जिन्होंने 663 पारियों में 14,803 रन बनाए हैं। पोलार्ड ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में 2 शतक और 70 अर्धशतक लगाए हैं।

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

खिलाड़ी	मैच	पारियां	रन	बेस्ट स्कोर	औसत	स्ट्राइक रेट	शतक	फिफ्टी	चौके	छक्के
● कीरोन पोलार्ड	746	663	14,803	104	31.76	151.02	2	70	923	1001
● जोस बटलर	517	487	14,572	131	35.02	146.74	9	102	1332	631
● क्रिस गेल	463	455	14,562	175	36.22	144.75	22	88	1132	1056
● एलेक्स हेल्स	528	523	14,449	119	29.91	144.51	7	92	1560	595
● डेविड वॉर्नर	439	438	14,284	135	37.29	140.77	10	118	1464	505

एशेज 2027: पुरुषों और महिलाओं के मुकाबलों का शेड्यूल जारी

लंदन ,एजेसीं। इंग्लैंड की पुरुष टीम अगले साल 18 जून से ट्रेंट ब्रिज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एशेज अभियान की शुरुआत करेगी। वहीं, महिला टीम 24 जून से अपने मल्टी-फॉर्मेट एशेज अभियान को शुरू करेगी। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने गुरुवार को 2027 सीरीज का पूरा शेड्यूल जारी किया है। इंग्लैंड की पुरुष टीम 18 जून को ट्रेंट ब्रिज के जिस मैदान पर पांच टेस्ट मुकाबलों की सीरीज शुरू करेगी, उसी मैदान पर उन्हें हाल ही में एशेज में सफलता मिली है और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहां खेले गए पिछले तीनों टेस्ट मैच जीते हैं। इसके बाद सीरीज के अगले मैच लॉर्ड्स, एजबेस्टन और यूटिलिटा बाउल (साउथेम्प्टन) में खेले जाएंगे। यूटिलिटा बाउल पहली बार पुरुषों के एशेज टेस्ट की मेजबानी करेगा। इस सीरीज का समापन 29 जुलाई से 'द किया ओवल' (लंदन) में होगा। दूसरी तरफ, इंग्लैंड की महिला टीम 24 जून को हेडिंग्ले में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसी के साथ साल 2001 के बाद लीड्स में पहला महिला एशेज टेस्ट मैच का आयोजन होगा, जिसके बाद ट्रेंट ब्रिज, द किया ओवल और एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में 3 से 9 जुलाई के बीच तीन टी20 मैच खेले जाएंगे। 13-20 जुलाई के बीच यूटिलिटा बाउल, लॉर्ड्स और एजबेस्टन में तीन वनडे मैच होंगे। पिछली घरेलू एशेज सीरीज में इंग्लैंड की महिला टीम ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अंक साझा किए थे और दोनों टीमें इस साल की शुरुआत में आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी आमने-सामने आई थीं।

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीमों के बीच एशेज सीरीज शेड्यूल-

7-10 जून: वॉर्म-अप मैच इंग्लैंड लायंस बनाम ऑस्ट्रेलिया, एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर (अगर ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचता है, तो इस मैच पर दोबारा विचार किया जाएगा)

- 21-25 जुलाई: चौथा एशेज टेस्ट (यूटिलिटा बाउल, साउथेम्प्टन)
- 29 जुलाई से 2 अगस्त: पांचवां एशेज टेस्ट (द किया ओवल, लंदन)

इंग्लैंड विमेंस वर्सेज ऑस्ट्रेलिया विमेंस - मेट्रो बैंक महिला एशेज

- 24-27 जून: एशेज टेस्ट मैच (हेडिंग्ले, लीड्स)
- 3 जुलाई: पहला वाइटैलिटी टी20 (ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम)
- 6 जुलाई: दूसरा वाइटैलिटी टी20 (द किया ओवल, लंदन)
- 9 जुलाई: तीसरा वाइटैलिटी टी20 (एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर)
- 13 जुलाई: पहला वनडे (यूटिलिटा बाउल, साउथेम्प्टन)
- 16 जुलाई: दूसरा वनडे (लॉर्ड्स, लंदन)
- 20 जुलाई: तीसरा वनडे (एजबेस्टन, बर्मिंघम)

ओवल में 9-13 जून के बीच खेला जाएगा खिताबी मुकाबला

लंदन ,एजेसीं। ओवल आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2027 के फाइनल की मेजबानी करेगा। यह मुकाबला 9 से 13 जून के बीच खेला जाएगा। ऐसा दूसरी बार होगा, जब यह मैदान चैंपियनशिप का फाइनल होस्ट करेगा। इससे पहले, साल 2023 में यहां खिताबी मुकाबला खेला जा चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी थी। पिछले साल, आईसीसी की सालाना कॉन्फ्रेंस के दौरान, ईसीबी को अगले तीन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (2027, 2029 और 2031) की मेजबानी के अधिकार मिले थे। डब्ल्यूटीसी फाइनल के शुरुआती तीन संस्करण इंग्लैंड के अलग-अलग वेन्यू पर आयोजित हुए थे। लॉर्ड्स ने साल 2025 का फाइनल होस्ट किया था, जिसमें साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी थी। न्यूजीलैंड ने साल 2021 में साउथेम्प्टन में भारत को 8 विकेट से हराकर पहला टाइटल जीता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में ओवल के मैदान पर 209 रन से जीत हासिल करते हुए ट्रॉफी जीती थी। आगामी फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे संस्करण का भी समापन करेगा। 2027 का संस्करण ऐतिहासिक रूप से और भी खास होगा, क्योंकि यह टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरे होने के जश्न के साथ होगा, जिससे खिताबी मैच की अहमियत और बढ़ जाएगी। ऑस्ट्रेलिया अभी डब्ल्यूटीसी रैंकिंग में 87.50 प्रतिशत अंकों के साथ शीर्ष पर है, जबकि मौजूदा चैंपियन साउथ अफ्रीका 75 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। न्यूजीलैंड (72.22), बांग्लादेश (58.33) और भारत (48.15) क्रमशः तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं, जबकि श्रीलंका (41.67), इंग्लैंड (24.36), वेस्टइंडीज (15) और पाकिस्तान (8.33) क्रमशः छठे, सातवें, आठवें और नौवें स्थान पर हैं। ईसीबी के कॉम्पिटिशन और बड़े इवेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर नील स्नोबॉल ने बताया कि इंग्लैंड को खेल के सबसे लंबे फॉर्मेट के इस ग्लोबल इवेंट को होस्ट करना जारी रखने पर गर्व है। उन्होंने कहा, 'हमें इंग्लैंड और वेल्स में अगले तीन आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल आयोजित करने का सम्मान मिला है। यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अगले साल भी 'द ओवल' ही इसकी मेजबानी करेगा। 'द ओवल' में 2023 का फाइनल ब्रॉडकास्टर्स और फैंस के बीच बहुत लोकप्रिय रहा था। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले साल का इवेंट भी बहुत खास होगा। यह देश और दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए एक शानदार मौका होगा कि वे पिछले दो वर्षों की दुनिया की दो सबसे बेहतरीन टेस्ट टीमों को एक बड़े इवेंट में आमने-सामने खेलते हुए देख सकें। '

भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज का संभावित शेड्यूल सामने आया

नई दिल्ली,एजेसीं। भारत और अफगानिस्तान के बीच सितंबर में 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है। यह पहला मौका होगा, जब अफगानिस्तान टी20 में भारत की मेजबानी भारत में ही करेगी। इस सीरीज की संभावित शेड्यूल सामने आई है। क्रिकइन्फो के मुताबिक, भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 सीरीज अरुण जेटली स्टेडियम में 13, 15 और 17 सितंबर को हो सकती है। मैचों की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। यह पहला मौका है, जब कोई टीम भारतीय जमीन पर भारत की मेजबानी करेगी। अफगानिस्तान कुछ समय से भारत में ही अपने घरेलू मैच खेल रहा है। अफगानिस्तान ने अपने घरेलू मैच लखनऊ, देहरादून और ग्रेटर नोएडा में खेले हैं, लेकिन इन मैचों में कोई मैच भारत के खिलाफ नहीं था। भारत-अफगानिस्तान टी20, श्रीलंका टेस्ट दौरा, और एशियाई खेलों के बीच यह तय किया गया है। एशियाई खेल सितंबर में जापान में होंगे। बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टेस्ट 27 अगस्त को खत्म होने वाला है, जबकि एशियाई खेल 24 सितंबर से होंगे। अफगानिस्तान और भारत ने जून में एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेले थे। अफगानिस्तान के लिए यह विदेशी दौरा था। भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ न्यू चंडीगढ़ में खेले गए टेस्ट को तीसरे दिन ही एक पारी और 300 रनों से जीता और फिर वनडे सीरीज 3-0 से अपने नाम की। भारतीय टीम का टी20 विश्व कप 2026 में चैंपियन बनने के बाद इस फॉर्मेट में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम इंडिया को आयरलैंड के खिलाफ पहली बार टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। आयरलैंड ने भारत को अपने घर में 2-0 से हराया था। इसके बाद इंग्लैंड ने भारत को अपने घर में 5 टी20 मैचों की सीरीज में 4-0 से हराया। इन दो सीरीज में एक भी मैच जीतने में असफल रही भारतीय टीम के लिए जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज बेहद अहम है। बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर इस सीरीज में जीत दर्ज करना चाहेंगे।

'मैं गर्व के साथ विदा ले रहा हूं'

निकोलस ओटामेंडी ने किया इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान

नई दिल्ली ,एजेसीं। अर्जेंटीना के स्टार डिफेंडर निकोलस ओटामेंडी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह गर्व के साथ फुटबॉल से विदा ले रहे हैं। 38 वर्षीय डिफेंडर के अनुसार, उन्होंने नेशनल टीम की जर्सी पहनते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इस अनुभवी सेंटर-बैक खिलाड़ी ने 17 साल से ज्यादा समय तक अर्जेंटीना की ओर से खेलने के बाद रिटायरमेंट की घोषणा की है। ओटामेंडी ने अर्जेंटीना के लिए 139 मैच खेले और फीफा वर्ल्ड कप तथा दो कोपा अमेरिका खिताब जीते। उन्होंने अपने विदाई संदेश को अपने करियर का सबसे मुश्किल पल बताया। अर्जेंटीना की 'गोल्डन जेनरेशन' के अहम खिलाड़ी ओटामेंडी ने चार फीफा वर्ल्ड कप में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया और देश के सबसे सफल डिफेंडरों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई। ओटामेंडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'इंस्टाग्राम' पर लिखा, 'आज मुझे अपने पूरे करियर के सबसे मुश्किल शब्द लिखने पड़ रहे हैं।

'बच्चों के भविष्य और उम्मीदों को सुरक्षित रखने का समाधान निकालेंगे': सचिन तेंदुलकर

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज रहे सचिन तेंदुलकर ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर अपनी राय रखी है। तेंदुलकर ने कहा है कि हम सभी मिलकर ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और मजबूत हो। सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'मेरे पिता एक प्रोफेसर थे। वे कई युवा छात्रों के लिए एक मार्गदर्शक और सलाहकार थे। उन्होंने मुझे शुरू से ही एक बात सिखाई थी कि असफलता ठीक है, लेकिन चीटिंग करना नहीं। कभी भी शॉर्टकट न अपनाएं।' उन्होंने आगे लिखा, 'समाज में बड़े होने के नाते, हमारी जिम्मेदारी है कि हम संस्कृति को सही दिशा दें। जो समाज मेहनत के बजाय नतीजों को ज्यादा अहमियत देता है, वह काबिलियत के बजाय शॉर्टकट को चुनता है। आज, जब छात्र निराश महसूस करते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत का उन्हें फल नहीं मिला, तो उनकी निराशा समझ में आती है। हम सभी को मिलकर यह पक्का करना चाहिए कि उन्हें दोबारा ऐसा महसूस न हो। ' तेंदुलकर ने लिखा, 'युवा भारत सपनों और ऊर्जा से भरा हुआ है।

वे हमारी सफलता का आधार हैं। एक समाज के तौर पर, माता-पिता, शिक्षक, दोस्त, रिश्तेदार, स्कूल और प्रशासक–हम सभी की एक बड़ी जिम्मेदारी है और अलग-अलग भूमिकाएं हैं ताकि हमारे युवा हमेशा उत्साहित और ऊर्जावान बने रहें। ' उन्होंने लिखा, 'हमें एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां कड़ी मेहनत को सराहा जाए, ईमानदारी को बढ़ावा मिले और काबिलियत की जीत हो। मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर ऐसे समाधान निकालेंगे जो हमारे बच्चों के भविष्य को मजबूत करेंगे और उनकी उम्मीदों को सुरक्षित रखेंगे। जय हिंद। ' सचिन तेंदुलकर देश के करोड़ों युवाओं की प्रेरणा है।

बार्सिलोना की बढ़ी मुश्किलें

चोट की वजह से कई महीनों तक मैदान से दूर रह सकते हैं फ्रेंकी डी जोंग

मैड्रिड ,एजेसीं। स्पेन के मशहूर फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार मिडफील्डर फ्रेंकी डी जोंग घुटने की गंभीर चोट के कारण कई महीनों तक मैदान से दूर रह सकते हैं। फ्रेंकी को यह चोट फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दौरान नीदरलैंड्स की ओर से खेलते हुए लगी थी। कई दिनों से स्पेनिश मीडिया में डी जोंग की चोट को लेकर खबरें चल रही थीं। अब बार्सिलोना ने आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि कर दी है। क्लब ने बताया कि जांच में पता चला है कि डी जोंग के दाएं घुटने की मेडियल कोलेटरल लिगामेंट (एमसीएल) में चोट लगी है। बार्सिलोना ने अपने बयान में कहा कि डी जोंग की अभी सर्जरी नहीं की जाएगी। वह क्लब के मेडिकल स्टाफ की निगरानी में बिना ऑपरेशन वाले इलाज (कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट) के जरिए ठीक होने की कोशिश करेंगे। अगले कुछ हफ्तों में उनकी रिकवरी पर लगातार नजर रखी जाएगी और उसके बाद ही डी जोंग की वापसी को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। 29 साल के डी जोंग बार्सिलोना के अहम खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनकी चोट से टीम की मिडफील्ड को बड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि, उनकी वापसी में कितना समय लगेगा, यह इलाज और रिकवरी की गति पर निर्भर करेगा। स्पेनिश अखबार 'एल मुंडो डेपोर्टिवो' की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर डी जोंग की सर्जरी करनी पड़ती है तो उन्हें ठीक होने में करीब चार महीने लग सकते हैं। वहीं, अगर बिना सर्जरी के इलाज सफल रहता है तो उनके मैदान पर लौटने का समय कम हो सकता है। फिर भी माना जा रहा है कि वह नए सीजन की शुरुआत में टीम के साथ नहीं खेल पाएंगे। बार्सिलोना का नया सीजन 15 अगस्त से शुरू होने वाला है। डी जोंग की चोट को लेकर बार्सिलोना और नीदरलैंड्स फुटबॉल टीम के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई हैं।

मैहर के सरकारी स्कूलों में शुरू होगी NEET-JEE की नि:शुल्क कोचिंग

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। मैहर जिले के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना अब और आसान होने जा रहा है। कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स विषयों की प्रतियोगी परीक्षा आधारित तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए जिले के उत्कृष्ट शिक्षकों का विशेष समूह तैयार किया जाएगा कार्यक्रम में देश की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्था एलेन का सहयोग लिया जाएगा संस्था चयनित शिक्षकों को प्रशिक्षण देगी तथा अपनी अध्ययन सामग्री और टेक्स्ट बुक्स जिले के सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों में उपलब्ध कराएगी जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री मिल सके। कलेक्टर ने कहा कि यदि विद्यार्थियों को 11वीं से ही सही मार्गदर्शन और नियमित कोचिंग मिले तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है इसी उद्देश्य से अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन किया जाएगा उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से आने वाले वर्षों में मैहर के अधिक से अधिक विद्यार्थी आईआईटी, एनआईटी और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त कर जिले का नाम रोशन करेंगे।

युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

सोनम वांगचुक से केंद्रीय मंत्रियों की सकारात्मक चर्चा के बाद अनशन समाप्त, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई का मुख्यमंत्री ने दिया भरोसा

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों से जुड़े विषयों को सरकार गंभीरता से ले रही है और परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय एवं मजबूत बनाने के लिए लगातार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा एवं केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। इस दौरान विद्यार्थियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार की पहल, दृष्टिकोण और आगामी योजनाओं की रूपरेखा साझा की गई मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्रियों और सोनम वांगचुक के बीच हुई चर्चा सकारात्मक एवं सार्थक रही। बातचीत के बाद वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करने का निर्णय लिया मुख्यमंत्री ने इसे संवाद और समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान निकालना सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं और विद्यार्थियों की चिंताओं को समझते हुए सरकार लगातार उनके हितों में फैसले ले रही है उन्होंने कहा कि देश का युवा वर्ग राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना सरकार की जिम्मेदारी है।

परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने पर सरकार का फोकस: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं विद्यार्थियों की मेहनत, समय और भविष्य को प्रभावित करती हैं ऐसे मामलों के प्रति सरकार पूरी तरह गंभीर है और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी उपायों, बेहतर प्रबंधन और प्रभावी निगरानी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक विद्यार्थी को निष्पक्ष अवसर मिले और वह अपनी योग्यता एवं मेहनत के आधार पर सफलता प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी के साथ अन्याय न हो, इसके लिए केंद्र सरकार समय-समय पर आवश्यक सुधार कर रही है। परीक्षा प्रणाली में सुधार के साथ-साथ विद्यार्थियों की शिकायतों के समाधान के लिए भी प्रभावी तंत्र विकसित किया जा रहा है।

युवाओं के हितों को लेकर सरकार संवेदनशील: डॉ. मोहन यादव ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाएं और उनकी समस्याएं सरकार के लिए महत्वपूर्ण हैं। रोजगार, शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषयों पर सरकार लगातार काम कर रही है उन्होंने कहा कि युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें सुरक्षित भविष्य प्रदान करना केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु विद्यार्थी और युवा हैं। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार, कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य को आकार देने का प्रयास करते हैं ऐसे में परीक्षा व्यवस्था का निष्पक्ष और पारदर्शी होना अत्यंत आवश्यक है। सरकार इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निरंतर सुधारात्मक कदम उठा रही है।

संवाद से निकलेगा समाधान का रास्ता: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार सभी वर्गों की बात सुनने और समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि किसी भी मुद्दे का स्थायी समाधान संवाद और आपसी समझ से ही संभव है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों द्वारा सोनम वांगचुक से की गई चर्चा को इसी दिशा में एक सकारात्मक पहल बताया उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की भावनाओं और चिंताओं का सम्मान करती है और उनके हितों की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है ।

सतना के उपयंत्री सतीश समेले को हाईकोर्ट से राहत अटैचमेंट के आदेश पर रोक; सीईओ ने अनुशासनहीनता

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सतना जिले की जनपद पंचायत मझगवां के संविदा उपयंत्री सतीश समेले को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सीईओ के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्हें शासकीय कार्यों से अलग कर दूसरे कार्यालय से अटैच किया गया था इस फैसले के बाद पंचायत विभाग में फिर हलचल तेज हो गई है जिला पंचायत सीईओ शैलेंद्र सिंह ने 7 जुलाई को चार पेज का आदेश जारी किया था इसमें सतीश समेले को सभी फील्ड कार्यों से हटाकर कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकीय संभाग, सतना कार्यालय से अटैच कर दिया गया था आदेश में लगाए गए थे कई आरोप सीईओ के आदेश में सतीश समेले पर सरकारी कार्यों के निरीक्षण के दौरान बंदूक लेकर जाने, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना, शासकीय कार्यों में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने और आचरण नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे इन्हीं आरोपों के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से फील्ड की जिम्मेदारियों से अलग किया गया था सतीश समेले ने सीईओ के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए अटैचमेंट के आदेश पर रोक लगा दी कार्यालय से अटैच किए जाने के बाद सतीश समेले ने मीडिया के सामने पंचायत से लेकर भोपाल तक कथित कमीशनखोरी के नेटवर्क का खुलासा करने का दावा किया था उन्होंने कहा था कि उनके पास इस मामले से जुड़े दस्तावेजी सबूत हैं जिन्हें वे हाईकोर्ट में पेश करेंगे। उनके इन आरोपों के बाद यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना था।

दो माह से राशन नहीं मिलने पर ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। जिले की ग्राम पंचायत डांडी के ग्रामीणों ने शुक्रवार को राशन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया ग्रामीणों ने नारेबाजी करते हुए खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें पिछले दो माह से राशन नहीं मिला है। उनका कहना है कि मई और जून माह का खाद्यान्न अब तक लंबित है शुक्रवार को जब जुलाई माह का राशन वितरण शुरू किया गया तो ग्रामीणों ने पहले बकाया राशन उपलब्ध कराने की मांग रखी मांग पूरी नहीं होने पर वे राशन दुकान से निकलकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गए ग्रामीणों ने सेल्समैन बालेंद्र प्रजापति पर राशन वितरण में लापरवाही और गड़बड़ी के आरोप लगाए उनका कहना है कि इससे पहले भी राशन वितरण में अनियमितता की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। ग्रामीण लक्ष्मी दाहिया सहित अन्य लोगों ने बताया कि दो माह से राशन नहीं मिलने के कारण गरीब परिवारों को भोजन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है उन्होंने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और जल्द से जल्द लंबित खाद्यान्न उपलब्ध कराने की मांग की। इस दौरान मैहर कांग्रेस नगर अध्यक्ष प्रभात द्विवेदी 'दद्दा' ने कहा कि यदि पात्र परिवारों को तत्काल राशन उपलब्ध नहीं कराया गया और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

NEET पेपर लीक के विरोध में सतना कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश में पुलिस से झड़प

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। NEET पेपर लीक मामले के विरोध में शुक्रवार को युवक कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं ने सतना जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन किया प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया प्रदर्शन को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को निर्धारित स्थान पर रोकने की कोशिश की इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच रस्साकशी और धक्का-मुक्की हुई पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था में सुधार और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई कांग्रेस नेत्री रश्मि सिंह ने भी प्रदर्शन में पहुंचकर छात्रों की मांगों का समर्थन किया उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की अनदेखी नहीं की जा सकती और सरकार को इस मामले में जवाब देना होगा। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन के दौरान स्थिति नियंत्रण में रही वहीं प्रदर्शनकारियों की ओर से पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाने और छीना-झपटी की सूचना भी सामने आई है प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

मानव सेवा के लिए रक्तवीर रविवार को करेंगे रक्तदान, सतना में आयोजित होगा शिविर

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। मानव सेवा और जरूरतमंद मरीजों की सहायता के उद्देश्य से सार्थक सेवा फाउंडेशन एवं सिंधु विकास समिति द्वारा रविवार 26 जुलाई को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है यह शिविर कृष्ण नगर स्थित सरस्वती विद्यालय में आयोजित होगा आयोजक मंडल के आशीष मोगिया, सुजाता शर्मा एवं विनोद गेलानी ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि रक्तदान शिविर का आयोजन प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया जाएगा शिविर में बड़ी संख्या में रक्तवीर एवं मातृशक्ति मानवता की सेवा के लिए रक्तदान करेंगे। कार्यक्रम में ी मणिकांत माहेश्वरी (अध्यक्ष, हिन्दू पर्व समन्वय समिति) की गरिमामय उपस्थिति रहेगी आयोजकों ने बताया कि रक्तदान एक पुनीत कार्य है जिससे जरूरतमंद मरीजों को जीवन बचाने में सहायता मिलती है उन्होंने समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में शिविर में पहुंचकर रक्तदान करें और मानव सेवा के इस अभियान में सहभागी बनें इस अवसर पर आशीष मोगिया, विनोद गेलानी, सुजाता शर्मा, स्वप्ना वास्तव, आकाश बनर्जी, मोना चोपड़ा, राखी होतचंदानी, डॉ. मनीषा सोई और अनिल मोटवानी सहित अन्य सदस्यों ने आमजन से रक्तदान कर मानवता की सेवा करने का आह्वान किया है।

नशामुक्त समाज के संदेश के साथ सतना पुलिस ने निकाली जागरूकता मैराथन, पुलिसकर्मियों ने लिया नशे से दूर रहने का संकल्प

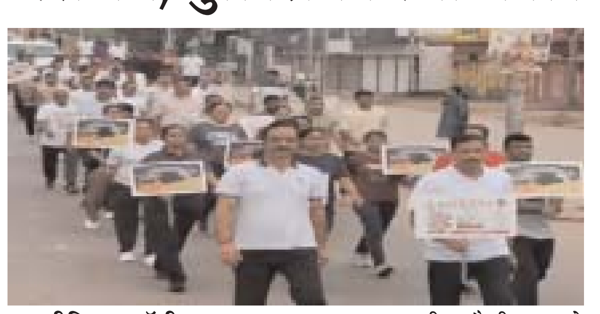

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। समाज को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने और नशामुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से सतना पुलिस द्वारा शुक्रवार को 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान के तहत जागरूकता मैराथन रैली का आयोजन किया गया। मैराथन के माध्यम से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने आम लोगों को नशे से दूर रहने तथा स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया जागरूकता मैराथन की शुरुआत पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड से हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सेमरिया चौराहा पहुंचकर समाप्त हुई रैली में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और जवान शामिल हुए हाथों में नशामुक्ति से संबंधित संदेश लिखे पोस्टर लेकर पुलिसकर्मियों ने लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया।

पुलिसकर्मियों ने लिया नशे से दूर रहने का संकल्प: मैराथन शुरू होने से पहले पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई पुलिसकर्मियों ने संकल्प लिया कि वे स्वयं नशे से दूर रहेंगे और समाज के अन्य लोगों को भी नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेंगे उन्होंने नशामुक्त समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया ।

नशा अपराधों का बड़ा कारण: एडिशनल एसपी: एडिशनल एसपी प्रेमलाल कुर्वे ने कहा कि पुलिस विभाग में काम करने वाले अधिकारी और जवान प्रतिदिन नशे से जुड़े अपराधों और उसके दुष्परिणामों को देखते हैं उन्होंने कहा कि कई बार नशे की आदत व्यक्ति को अपराध की ओर ले जाती है जिसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है उन्होंने कहा कि पुलिस की भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और लोगों को नशे जैसी सामाजिक बुराई से बचाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना भी पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

सतना में जलावर्धन योजना पर सवाल, टिकुरिया टोला में बदबूदार और कीड़े युक्त पानी की सप्लाई का आरोप

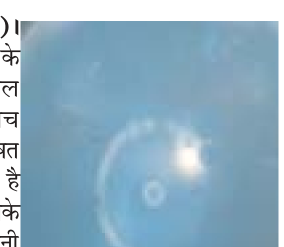

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। नगर निगम की जलावर्धन योजना के तहत शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के दावों के बीच टिकुरिया टोला क्षेत्र के लोगों ने दूषित पानी की सप्लाई का आरोप लगाया है स्थानीय लोगों का कहना है कि उनके घरों में बदबूदार और कीड़े युक्त पानी पहुंच रहा है, जिससे स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है क्षेत्रवासियों के अनुसार पिछले कुछ समय से नलों में आने वाले पानी की गुणवत्ता खराब बनी हुई है पानी से दुर्गंध आने के साथ उसमें गंदगी और छोटे-छोटे कीड़े दिखाई देने की शिकायत सामने आई है लोगों का कहना है कि इस पानी का उपयोग करने से गंभीर बीमारियों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इस समस्या की जानकारी नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को भी दी गई है लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। लोगों ने मांग की है कि जल सप्लाई व्यवस्था की जांच कर पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए नागरिकों ने दूषित पानी से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासन को समय रहते कार्रवाई करनी चाहिए।

कलेक्टर ने शहर की सड़कों का किया निरीक्षण, निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

जर्जर मार्गों की स्थिति सुधारने पर जोर, गुणवत्ता और समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने अधिकारियों को दिए निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और नागरिकों को सुगम आवागमन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने शुक्रवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण, मरम्मत कार्यों और मार्गों की वर्तमान स्थिति का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि शहर में चल रहे सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा सड़कें नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं इसलिए इनके निर्माण और रखरखाव में विशेष गंभीरता बरती जाना आवश्यक है। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने सबसे पहले एकेएस क्रिस्तकुला रोड एवं गढ़िया टोला क्षेत्र का निरीक्षण किया उन्होंने मौके पर पहुंचकर सड़क की स्थिति का अवलोकन किया और क्षेत्र में आवागमन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मार्ग की स्थिति में शीघ्र सुधार किया जाए उन्होंने कहा कि जहां सड़क निर्माण की आवश्यकता है वहां नवीन निर्माण कार्य कराया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर और सुरक्षित आवागमन सुविधा मिल सके। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि सड़क निर्माण के दौरान तकनीकी मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए उन्होंने कहा कि मजबूत और गुणवत्तापूर्ण सड़कें लंबे समय तक नागरिकों को सुविधा प्रदान करती हैं और बार-बार मरम्मत की आवश्यकता को कम करती हैं। इसके बाद कलेक्टर ने नजीराबाद रोड और कोठी मोड़ क्षेत्र का निरीक्षण किया यहां उन्होंने सड़क की जर्जर स्थिति को देखते हुए अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कार्य प्रारंभ कर शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि खराब सड़कों के कारण आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है इसलिए ऐसे मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर दुरुस्त किया जाए।

प्राचार्य ने थाने में दर्ज कराई शिकायत, विद्यालय परिसर में पहले भी असामाजिक गतिविधियों का आरोप

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। जिले के नादन देहात थाना क्षेत्र स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरियारी में असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी करने का मामला सामने आया है घटना के बाद विद्यालय प्रबंधन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हुए दो युवकों को हिरासत में लिया है जानकारी के अनुसार घटना बुधवार शाम स्कूल की छुट्टी के बाद हुई शाम करीब 5:30 से 6 बजे के बीच अज्ञात लोगों ने विद्यालय परिसर में पत्थर फेंके। अगले दिन गुरुवार को जब प्राचार्य स्कूल पहुंचे तो परिसर में पत्थर पड़े मिले, जिसके बाद घटना की जानकारी हुई विद्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। विद्यालय के प्राचार्य रामसूचित यादव ने बताया कि इस तरह की घटना पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले भी कुछ असामाजिक तत्व विद्यालय परिसर में शराब की बोतलें तोड़कर गंदगी फैला चुके हैं लगातार हो रही घटनाओं से स्कूल की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राचार्य ने नादन देहात थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को दो युवकों को हिरासत में लिया नादन देहात थाना प्रभारी पंचराज सिंह ने बताया कि मामले में जांच जारी है।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया प्रकाशन रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय प्रभात बिहार कॉलोनी सतना से प्रकाशित, संपादक संदीप द्विवेदी आर.एन.आई नं.एमपीएचआईएन/2021/81683
प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9407132714, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार, सभी विवादो का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।